प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

खुद पर विश्वास रखें। आपका विश्वास जितना मजबूत होगा, संदेह उतना ही कम होता जाएगा।

गौर गोपालदास

वर्ष-08, अंक - 03 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 16 अक्टूबर 2025 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सड़क नहीं पूरा सिस्टम ढह रहा है...!

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

पिछले दिनों घटित कुछ घटनाओं ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। जिसके बाद आम आदमी यह सोचने को मजबूर है कि, क्या यह वही 21वीं सदी है जिसकी कल्पना 20वीं सदी में की गई थी। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का नारा दिया गया था। पूरा सरकारी सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है कि, सीनियर आईपीएस अधिकारी तक सुसाइड कर रहे हैं। सड़क, मिट्टी की तरह बह रही है। सरकारी डॉक्टर कमीशन के खेल में जहरीली दवाइयां लिख रहे हैं और अस्पताल में बच्चों को चूहे कुतर रहे हैं। जज के घर प्रचुर मात्रा में अधजले नोटों की बोरियां मिल रही है और सुप्रीम कोर्ट तक में वकील, जज पर जूता उछालने से भी नहीं डर रहे हैं। ऐसे में आम आदमी यही सोच रहा है महात्मा गांधी के इस देश में गांधी छाप नोटों के लिए आदमी का पतन और कितना होगा...?

हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी एडीजीपी पूरन कुमार ने आत्महत्या कर ली जिसके बाद यह केश पूरे देश में चर्चित हो गया। 6 अक्टूबर को रोहतक में साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप लाठर ने पूरन कुमार के गनर सुशील को रिश्वत लेते पकड़ा था और अगले ही दिन पूरन कुमार ने जान दे दी। इसके बाद 13 अक्टूबंर को संदीप लाठर ने भी खुदकुशी कर ली। जिसके बाद पूरे देश में यह केश चर्चित है और आम चर्चा का विषय बना हुआ है कि, भ्रष्टाचार की जड़े कितनी फैल चुकी है। जहां आईपीएस अधिकारी के साथ ही एएसआई तक के अधिकारी भी भ्रष्टाचार की जद् में आ रहे हैं और आत्मघाती कदम उठाने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी घटना भोपाल के सुखी सेवनियां ओवर ब्रिज के पास बाईपास रोड ताश के पत्तों की तरह धस गया और सड़क के किनारे लगभग 60 मीटर लंबा और 8 मीटर से अधिक का हिस्सा धस गया। सड़क के उस हिस्से के फोटो को देखने के बाद आम आदमी का यही कहना है कि, इस सड़क के निर्माण में आटे में नमक नहीं नमक में आटे जितना भ्रष्टाचार हुआ होगा। इतनी घटिया स्तर की रोड वह भी प्रदेश की राजधानी में बनी है तो प्रदेश के अन्य हिस्सों की सहज ही कल्पना की जा सकती है। सड़क धसने के बाद विभाग लीपा पोती पर जुट गया है और जांच बिठा दी गई है। जिसमें कुछ लापरवाही के बिंदु को ही रेखांकित किया गया है जैसे आर ई वाल का निर्माण निर्धारित तकनीकी मानको अनुसार नहीं किया गया, उपयोग की गई मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, बेकमेन्ट में आवश्यक स्टोन कीपिंग का कार्य नहीं किया गया था। अब सवाल यह उठता है कि, सड़क के धसने के बाद उसमें कमियां निकाली गई तो सड़क को बनाते वक्त जांच क्यों नहीं की गई...? यही नहीं जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि, पूर्व में जांच की गई थी जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई थी। जिससे यह सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि, किस प्रकार की जांच की गई होगी...? तथा सब कुछ अच्छा बताने के लिए कितना भ्रष्टाचार किया गया होगा...? आम आदमी यह सोचने को मजबूर है कि इतना कुछ, बिना कुछ लिए दिए संभव नहीं हो सकता है।

सिस्टम के भ्रष्टाचार की भेंट छिंदवाड़ा के 23 नव निहालों को अपनी जान चढ़ाना पड़ी जहां डॉक्टर ने महज कुछ रूपयो के कमिशन के खातिर जहरीले कफ सिरप लिखने से परहेज नहीं किया। जांच में नित नए चैंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। आरोपित डॉक्टर प्रवीण सोनी को श्री सन फार्मास्युटिकल के कोल्डड्रिंक कफ सिरप की 25.54 रुपए कीमत वाली प्रत्येक बोतल पर ढाई रुपए का कमीशन मिलता था। यानी एक बोतल पर महज 10 प्रतिशत कमीशन के लिए डॉक्टर प्रवीण सोनी ने अपना जमीर बेच दिया। जबकि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने दिसंबर 2023 में ही राष्ट्रियव्यापी निर्देश जारी किए थे। जिसमें 4 साल से कम आयु के बच्चों को फिक्स्ड डोज कॉबिनेशन (एफडीसी) दवाई न लिखने की चेतावनी दी थी।

देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के प्रतिष्ठ एम वाय हॉस्पिटल में चूहो की कुतर कुतर की गूंज पूरे देश में सुनाई दी और वहां जांच के नाम पर अब भी लीपा पोती जारी है। वहां चूहों ने न केवल दोनों नवजात बच्चों को कुतरा बल्कि पूरे सरकारी सिस्टम को ही कुतर कर रख दिया। वहीं अन्य घटनाओं के साथ ही न्यायपालिका में घटित दो घटनाओं ने भी देश को सोचने पर विवस कर दिया है कि आम आदमी कहीं भी सुरक्षित नहीं है, न सड़क, रेल और हवाई यात्रा में और न ही सिस्टम के सरकारी अस्पताल में जहां दवा के नाम पर जहर दिया जाता है और अबोध बच्चों को चूहे कुतर देते हैं। ऐसे में सरकारी दावे आम आदमी को, सरकार के द्वारा आम जनता के साथ किया जाना मजाक ही लगता है।

रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा

इंदौर/ग्वालियर।

मध्य प्रदेश लोकायुक्त टीम ने सेवानिवृत्त आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के इंदौर और ग्वालियर स्थित आठ ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई एक गोपनीय शिकायत के आधार पर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भदौरिया ने अपनी आय से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की है।

प्रारंभिक जांच में ही लगभग 8 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति और निवेश के दस्तावेज सामने आए हैं, जबकि अधिकारी की वैध आय केवल 2 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

लोकायुक्त टीम ने इंदौर के कैलाश कुंज, बिजनेस स्काई पार्क, अवि ग्रीन, काउंटी वॉक कॉलोनी तथा ग्वालियर के इंद्रमणि नगर में छापे मारे। तलाशी के दौरान टीम को भारी मात्रा में नकदी, गहने, विदेशी मुद्रा और कीमती वस्तुएं मिलीं।

छापेमारी के दौरान लोकायुक्त टीम को भारी मात्रा में नकदी, गहने, विदेशी मुद्रा और महंगी वस्तुएं मिलीं। इनमें डेढ़ किलो सोने की बार, 1 किलो सोने के गहने, 4 किलो चांदी के जेवर, 75 लाख नकद, महंगी घड़ियां, इत्र और साड़ियां शामिल हैं। इसके अलावा एक रिवॉल्वर, एक रायफल, 500 यूरो के 10 नोट (कुल 5,000 यूरो, लगभग साढ़े 4 लाख मूल्य) भी बरामद किए गए। टीम को दो फ्लैट, एक निर्माणाधीन बंगला, कई बीघा कृषि भूमि, विभिन्न बैंकों में पांच लॉकर और कई खाते भी मिले हैं।

जांच में यह भी सामने आया है कि भदौरिया ने अपने बेटे सूर्यांश और बेटी अपूर्वा के नाम से फिल्म निर्माण में निवेश किया था। वहीं, गुजरात में सक्रिय उनके समधी ए.के. सिंह का नाम अवैध शराब कारोबार से जुड़ा बताया जा रहा है।

भदौरिया वर्ष 1987 में आबकारी विभाग में भर्ती हुए थे और अगस्त 2025 में सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 2020 में शराब ठेका नीलामी में लापरवाही के आरोप में वे निलंबित भी हो चुके हैं।

लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान के अनुसार, अब तक मिली संपत्ति भदौरिया की वैध आय से कई गुना अधिक है और जांच जारी है। यह मामला आय से लगभग 300 प्रतिशत अधिक संपत्ति का है, जिसका आंकड़ा आगे और बढ़ सकता है।

भारत को अब विश्वस्तरीय रेलवे प्रदर्शनी आयोजित करनी चाहिए : वैष्णव

नई दिल्ली, एजेंसी।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारतीय रेल ने जबरदस्त प्रगति की है और इसके नतीजे अब साफ दिखाई दे रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इन 11 वर्षों में 35 हजार किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई गई है और 46 हजार किलोमीटर रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया है और आज उसके शानदार परिणाम देश के सामने हैं। इस अवधि में 40 हजार नए रेल कोच बनाए गए हैं, जो भारत की तकनीकी और निर्माण क्षमता को दर्शाते हैं।

वैष्णव ने कहा कि यह उपलब्धियां भारतीय रेल के परिवर्तन और एक आधुनिक, टिकाऊ तथा यात्री-हितैषी परिवहन प्रणाली की दिशा में सरकार की दूरदर्शी सोच को दर्शाती हैं। उन्होंने बताया कि देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना पर तेजी से कार्य चल रहा है और अब तक 325 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है।

उन्होंने कहा, मैं सूरत और मोरा स्टेशनों पर गया था। यह 2027 में शुरू होने वाले पहले खंड का हिस्सा होंगे।÷ वैष्णव ने बताया कि वर्तमान में भारत में 156 वंदे भारत सेवाएं, 30 अमृत भारत सेवाएं और 4 नमो भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं, जो यात्रियों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हैं।

रेल मंत्री ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) को यह आयोजन करने के लिए धन्यवाद दिया और सुझाव दिया कि भारत को अब एक विश्वस्तरीय रेलवे प्रदर्शनी आयोजित करनी चाहिए, जो जर्मनी की 'इनोट्रांस' प्रदर्शनी से भी बड़ी हो।

पाकिस्तान के लिए आत्मघाती कदम होगा – पहलगाम जैसा हमला करने की आशंका

जम्मू। पाकिस्तान की ताकत इस काबिल नहीं है कि वह भारत से सीधे मुकाबला कर सके। यही वजह है कि वह समय-समय पर भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहता है। पश्चिमी सेना कमान के वरिष्ठ अधिकारी मनोज कुमार कटियार ने भी ऐसी ही साजिश की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फिर से पहलगाम जैसी आतंकी साजिश रच सकता है, क्योंकि उसके पास भारत से सीधे युद्ध करने की न क्षमता है और न ही हिम्मत। जनरल कटियार ने स्पष्ट कहा कि अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो भारत की जवाबी कार्रवाई और भी घातक होगी। उन्होंने कहा, ÷यदि वे कुछ करते हैं तो हमारा जवाब पहले से कहीं अधिक घातक होगा। इसमें कोई शक नहीं। हम पूरी तरह तैयार हैं और मुझे भरोसा है कि अगली कार्रवाई निर्णायक होगी।÷ जम्मू में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह चेतावनी दी। उन्होंने आगे कहा कि अभियान सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया था। इसके तहत पाकिस्तान की चौकियों और हवाई ठिकानों को नष्ट किया गया था। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि वह फिर कुछ करने की कोशिश कर सकता है। कटियार ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपनी दुर्भावनापूर्ण नीतियों से बाज नहीं आएगा, इसलिए सतर्कता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है और उसे जनता का पूरा समर्थन प्राप्त है। यही कारण है कि अभियान सिंदूर के दौरान हम पाकिस्तान को करारी चोट देने में सफल रहे। रिपोर्ट में उल्लेख है कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय व्यक्ति की जान चली गई थी। इसके बाद भारत ने 7 मई से अभियान सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान व पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर में आतंक के ढांचे को निशाना बनाया गया।

एआईएडीएमके सांसद का विवादित बयान – स्टालिन अब फ्री पत्नी भी बांट देंगे

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी ने तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्षी पार्टी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सी. वी. षणमुगम ने मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन पर निशाना साधते हुए विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया है।

बताया जा रहा है कि षणमुगम ने यह टिप्पणी पार्टी की बूथ समिति बैठक के दौरान की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लगभग डेढ़ मिनट के इस वीडियो में वे कहते नजर आए कि जब हमारी सरकार थी, हमने बिना मांगे ढाई हजार रुपये बांटे थे, लेकिन स्टालिन ने पांच हजार रुपये की मांग की थी। सत्ता में आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं दिया। अब चुनाव नजदीक हैं, तो वे लैपटॉप, मिक्सी, ग्राइंडर, मिनी बस और यहां तक कि जानवर भी बांट देंगे, या फिर फ्री पत्नी की घोषणा भी कर सकते हैं।

इस बयान के सामने आते ही द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) नेताओं और महिला मंत्रियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। तमिलनाडु की समाज कल्याण मंत्री पी. गीता जीवन ने कहा कि षणमुगम ने महिलाओं की तुलना मुफ्त चीजों से करके न केवल उनका अपमान किया है, बल्कि पूरी महिला समाज का अनादर किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति इंसान कहलाने लायक भी नहीं है।

डीएमके ने इस बयान की आधिकारिक रूप से कड़ी निंदा करते हुए कहा कि विपक्ष महिला सम्मान पर राजनीति कर रहा है और यह टिप्पणी तमिल समाज की संस्कृति के खिलाफ है। वहीं, महिला संगठनों और सोशल मीडिया पर भी सांसद के खिलाफ तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई उपयोगकर्ताओं ने इस बयान को महिलाओं के प्रति असम्मानजनक और असंवेदनशील बताया है।

सीबीआई की छापेमारी, साइबर ठगी मामले में तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी मामले में सोमवार को कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई सीबीआई के ऑपरेशन चक्र-5 के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करना है। इस दौरान एजेंसी ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह मामला गृह मंत्रालय के अंतर्गत साइबर समन्वय केंद्र द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर दर्ज किया गया था।

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि देशभर के हजारों लोगों को करोड़ों रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। आरोप है कि यह गिरोह सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप और एन्क्रिप्टेड संदेश मंचों के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन निवेश और पार्ट-टाइम नौकरी के झूठे वादों से फंसाकर उनसे भारी रकम वसूलता था। जांच में यह भी पता चला कि इस नेटवर्क में भारतीय और विदेशी दोनों तरह के लोग शामिल थे।

आरोपियों ने देशभर में, खासतौर पर बेंगलुरु में फर्जी कंपनियों का जाल बिछाया था। इन कंपनियों के जरिए ठगी से प्राप्त धन को अलग-अलग खातों में स्थानांतरित किया गया। कई निर्दोष लोगों को ई-कॉमर्स और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों में पार्ट-टाइम रोजगार का झांसा देकर कंपनी का निदेशक बनाया गया, ताकि फर्जी बैंक खाते और डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से धन का प्रवाह किया जा सके।

सीबीआई के अनुसार, अपराधियों ने एक संगठित और उन्नत साइबर ठगी प्रणाली अपनाई थी, जिसमें डिजिटल विज्ञापन, सामूहिक संदेश अभियान (एसएमएस कैंपेन) और सिम बॉक्स तकनीक का उपयोग कर फर्जी निवेश योजनाओं को प्रचारित किया गया। टेलीग्राम, व्हाट्सऐप और अन्य सोशल मीडिया मंचों पर लोगों से केवाईसी दस्तावेज लेकर फर्जी प्रोफाइल और कंपनियां बनाई गईं। इन कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोले गए, जिनमें पीड़ितों से ठगे गए रुपये जमा कराए जाते थे।

जांच से यह भी सामने आया है कि ठगों ने धन को कई स्तरों पर स्थानांतरित किया और भुगतान गेटवे, यूपीआई प्लेटफॉर्म तथा क्रिप्टो मुद्रा विनिमय केंद्रों के माध्यम से धन की हेराफेरी की। ठगी की रकम का बड़ा हिस्सा क्रिप्टो मुद्रा, सोना या गुप्त चैनलों के जरिए विदेश भेजा गया। सीबीआई ने पाया कि कई भारतीय नागरिक विदेशी संस्थाओं के निर्देश पर काम कर रहे थे, जो अवैध ऑनलाइन जुए और निवेश ठगी संचालन में शामिल थीं।

एजेंसी ने अब तक कई संदिग्ध बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की पहचान कर ली है, जो इस नेटवर्क से जुड़े हैं। यह मामला भारत और अन्य देशों में फैले एक विशाल साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का हिस्सा है। सीबीआई ने बताया कि इस मामले में अन्य भारतीय और विदेशी आरोपियों की तलाश जारी है तथा ठगी की रकम का पता लगाकर उसे फ्रीज करने की प्रक्रिया चल रही है। ऑपरेशन चक्र-5 के तहत एजेंसी का लक्ष्य ऐसे अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोहों को खत्म करना है, जो कई देशों में फैले हैं और भारतीय नागरिकों को निशाना बना रहे हैं।

नगर परिषद अध्यक्ष के पति पर जानलेवा हमला, एयरलिफ्ट की तैयारी

पन्ना। पन्ना जिले के देवेंद्रनगर नगर परिषद अध्यक्ष के पति ललित गुप्ता पर बुधवार देर शाम गोलीबारी हुई। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ललित गुप्ता को गंभीर अवस्था में पहले बिड़ला अस्पताल, सतना लाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें भोपाल रेफर करने की तैयारी शुरू कर दी है।

एसडीएम सिटी की अगुवाई में बना हरित गलियारा

घायल को भोपाल एयरलिफ्ट कराने के लिए एसडीएम सिटी राहुल सिलाड़िया की अगुवाई में प्रशासन ने बिड़ला अस्पताल से हवाई अड्डे तक हरित गलियारा (ग्रीन कॉरिडोर) बनाया। चूंकि सतना हवाई अड्डे पर सूर्यास्त के बाद उड़ान संभव नहीं होती, इसलिए निर्णय लिया गया कि ललित गुप्ता को रीवा हवाई अड्डे से भोपाल एयरलिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए बिड़ला अस्पताल से राष्ट्रीय राजमार्ग तक हरित गलियारा तैयार किया जा रहा है, ताकि एंबुलेंस को बिना बाधा रास्ता मिल सके।

बिड़ला अस्पताल में भाजपा नेताओं का जमावड़ा

घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विजय तिवारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मौके से ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से वीडियो कॉल पर बातचीत कराई। वीडी शर्मा ने घायल ललित गुप्ता से सीधे बात की और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

जब बागड़ ही खेत खाने लग जाए...

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हवाला लूट कांड में मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर बड़ी कार्यवाही की गई है। जिसमें पूर्व एसडीओपी पूजा पांडे समेत कुल 11 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

इन पर डकैती, गलत तरीके से रोकना, अपहरण और आपराधिक षडयंत्र रचने के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 (2), 126(2), 140(3) और 61 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद प्रकरण में एसडीओपी पूजा पांडे सहित पांच पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 6 आरोपी पुलिस कर्मी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जिसके बाद जन चर्चा बनी हुई है कि, जब बागड़ ही खेत खाने लग जाए तो फिर खेत किसके हवाले...?

अजब एमपी की गजब पुलिस की बात करे तो वह जब्त की गई सरकारी राशि को हड़पना चाहती थी। लेकिन मामला उजागर होने पर यह केस पुलिस की ही गले की हड्डी बन गया और ऐसे केस प्रदेश में कई जगह हो चुके हैं जहां पुलिस जब्त की गई राशि को कम बताती है। लुट जेसी बड़ी घटनाओं को छोटी-मोटी चोरी बताकर मामले को रफा-दफा करने

की कोशिश की जाती है। मध्य प्रदेश में अधिकांश पुलिस थाने और चौकिया भांजगाडी (आपसी सुलह) का केंद्र बन चुके हैं। जहां कई मामले थाने और चौकी के बाहर ही बिना एफआईआर दर्ज के सुलझा लिए जाते हैं और इसमें एक बड़ा हिस्सा पुलिस के साथ स्थानीय दबंग जिसे स्थानीय भाषा में (भांजगड़ियां) कहा जाता है के बीच बट जाता है।

क्या है मामला

एसडीओपी पूजा पांडे को जानकारी मिली थी कि, एक कार में करीब तीन करोड रुपए ले जाए जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ रात करीब डेढ बजे सिला देही में नाकाबंदी की ओर कार को रोककर उसमें रखी रकम पुलिस की गाड़ी में रख ली। इस कार्यवाही के खिलाफ कारोबारी और उसके सहयोगी साथियों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। आरोपी पुलिस कर्मियों ने हवाला की रकम आपस में बांटने की बात कही थी इसमें पुलिस के भी 1.5 करोड रुपए अपने पास रखना चाहते थे। यानी आधे पुलिसकर्मी और आधे कारोबारी के बीच बांटने का सौदा हुआ था। लेकिन बाद में कारोबारियो को कम रकम दी गई इससे नाराज होकर वे फिर थाने में पहुंचे। जब यह मामला मीडिया तक पहुंचा तो पूरी घटना का पर्दाफाश हो गया। वहीं इस मामले में नागपुर से दो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले तीन को गिरफ्तार आरोपियो को जबलपुर लाया गया जहां पूछताछ जारी हौ पूरे मामले में अब तक करीब ढाई करोड़ से ज्यादा की जब्ती हो चुकी है।

थांदला पुलिस भी किसी से कम नही

अजब एमपी की गजब पुलिस की बात करे तो झाबुआ जिले की पुलिस भी इसमें कही भी पिछे नही है। इसी प्रकार का मामला थांदला थाना क्षेत्र में हो चुका है जहां पुलिस चेकिंग में 99 लाख जप्त किए गए थे लेकिन हिसाब 79 लाख का ही मिला। बाकी 20 लाख रहस्य बन गए। वहीं थांदला थाना क्षेत्र में ही विगत दिनों एक बड़ी लूट को थांदला पुलिस ने मामूली चोरी बतला कर मामला को रफा दफा करने का प्रयास किया। ये ऐसे मामले है जो आम जनता के सामने आ पाए हैं। आम जनता का कहना है कि, पुलिस की कार्यप्रणाली को देखकर तो यही लगता है कि, इससे कई ज्यादा मामले तो पुलिस रफा-दफा ही कर देती है और वे जनता के सामने नहीं आ पाते हैं। कहते हैं कि, दो नंबर का काम ईमानदारी का काम होता है और इन मामलों में तो पुलिस अपनी चालाकी दिखाना चाहती थी। बराबर के बंटवारे का सौदा करने के बाद पलट गई और सारा खेल चौपट हो गया था।

चाबे जी, छब्बे जी बनने चले थे लेकिन दुबे जी बनकर रह गए। भंडारे में पूरी खाने गए थे पूरी तो ना मिली लेकिन चप्पल चोरी हो गई।

डेढ़ करोड़ पर दांव बनाया था लेकिन अब नौकरी बचाना भी मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में थांदला पुलिस का 20 लाख गबन में क्या होगा यह देखना भी दिलचस्प रहेगा।

स्कूल घटिया निर्माणः निर्माण एजेंसी व ठेकेदार मिलकर शासन के पैसों की कर रहे हैं बंदर बाट

माही की गूंज, खवासा। सुनील सोलंकी

एक तरफ प्रदेश सरकार बच्चों को हर सुविधा मिले इसी उद्देश्य को देखते हुए जहां भवन नहीं है वहां नए सिरे से अतिरिक्त स्कूल कक्ष के भवन के नाम से उनका नए सिरे से निर्माण ठेकेदार के मार्फत से करवाया जा रहा है। लेकिन निर्माण के नाम पर ठेकेदार व निर्माण एजेंसी के अधिकारी मिलकर अतिरिक्त कक्ष में निम्न व घटिया स्तर की सामग्री का इस्तेमाल करके बंदरबाट कर रहे हैं। जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस भवन की क्या दुर्दशा होगी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है।

कुछ ऐसा ही मामला कन्या स्कूल खवासा में सामने आया, जहां शासन द्वारा एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण करवाया जा रहा है। भवन की लागत 20 लाख रुपए है, निर्माण एजेंसी ग्रामीण यांत्रिक सेवा संभाग (आरईएस) झाबुआ है। तथा ठेका बामनिया के योगेश शर्मा को मिला हुआ है। लेकिन विभागीय अधिकारी व ठेकेदार मिलकर शासन के पैसों की बंदर बांट कर रहे हैं। तथा निम्न व घटिया स्तर का कार्य करके ठेकेदार घटिया स्तर का भवन बनाया जा रहा है। लेकिन फिर भी निरीक्षण करने वाले सब इंजीनियर, ठेकेदार के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे है। जिससे साफ प्रतीत होता है कि, इसमें विभागीय इंजीनियर, अधिकारी व ठेकेदार मिलकर भवन में निम्न व घटिया स्तर की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। मौके पर डस्ट चुरी के साथ निम्न घटिया स्तर की सीमेंट के साथ जंग लगे पुराने लोहे के सरिये से भवन का निर्माण कर दिया गया। अभी वर्तमान में भवन की छत भराई हो गई है लेकिन समय पर वहां भी पानी की तरी ही नहीं हो पा रही है। एसे में भवन में अभी से उसकी कमियां दिखाई दे रही है। विभागीय अधिकारी अगर निरीक्षण करके रिपोर्ट तैयार करें तो यहा कई तरह की कमियां इस भवन के अंदर दिखाई दे सकती है। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि, निरीक्षण करें तो कौन...? क्योंकि यहां तो सब भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। जिसके कारण ठेकेदार मजे से घटिया कार्य करके शासन के पैसों की बंदर बांट कर रहा है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन निकला

माही की गूंज ,सारंगी ,संजय उपाध्याय

संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी वर्ष में संपूर्ण राष्ट्र में संघ के निकल रहे पथ संचलनो की श्रृंखला में सारंगी में भी भव्य पथ संचलन निकला..जिसमें सारंगी नगर एवं मण्डल के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों से स्वयंसेवक शामिल हुए। श्री विजयादशमी उत्सव पथ संचलन में वक्ता के रूप में संघ के प्रचारक एवं रतलाम विभाग धर्म जागरण प्रमुख नमित भाईसाब आए, उन्होंने अपने उद्बोधन में संघ के प्रारंभ का वर्णन करते हुए बताया कि किस तरह संघ ने हिंदू समाज को संगठन करने का संकल्प धारण किया और यह आज 100 वर्ष पूर्ण कर रहा हैं । उन्होंने हिंदू समाज को भी साधुवाद देते हुए कहा यह हिंदू समाज का ही समर्पण है कि इस तरह के आयोजन संघ कर पा रहा हैं ।

अपने उद्बोधन में उन्होंने बताया कि शताब्दी वर्ष में संघ ने पंच परिवर्तन के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया है । स्व का बोध अर्थात स्वदेशी, नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण, सामाजिक समरसता एवं कुटुंब प्रबोधन..संघ के इन पांचों आग्रहों का विस्तार से वर्णन किया। संचलन में घोष के साथ कदमताल करते हुए निकले ,स्वयंसेवकों का नगर के हर घर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया कई जगह सामुहिक रूप से स्वागत मंच सजा कर स्वागत किया जिसमें नगर के आदिवासी समाज के युवाओं ने मंच से स्वागत किया, व्यापारी वर्ग,व व्यापारियों के प्रतिष्ठानों से ओर भारतीय पत्रकार संघ ने भी मंच लगा कर स्वागत किया। पथ संचलन सारंगी के छात्रावास मैदान से प्रारंभ होकर भैरवनाथ बस स्टैंड, गायत्री माता मंदिर, सदर बाजार, बस स्टैंड एवं चौपाटी होते हुए मंडी प्रांगण पहुंचा यहां पर पथ संचलन का समापन हुआ।

त्यौहार को देखते हुआ मिठाई, दूध, पनीर की नमूना कार्यवाही जारी

माही की गूंज, धार। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश के आदेशानुसार एवं कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में जिले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा आगामी आने वाले त्यौहार दीपावली आदि को देखते हुए खाद्य कारोबारियों, मिठाई मावा निर्माता विक्रेताओ की सघन जाँच अभियान जारी है। अभियान के तहत गत दिवस खाद्य सुरक्षा अधिकारी, निर्मला सोमकुंवर के द्वारा सतीश राय, सिमरन स्वीट्स, पीथमपुर सेक्टर 1 से मावा एवं मावा पेडा, लखीराम सैनी, सैनी स्वीट्स, पीथमपुर सेक्टर 1, से मावा कतली एवं रसगुल्ला, पर्वत सिंह सुनेर राधा स्वामी दूध डेयरी इंडोरामा सेक्टर 3 पीथमपुर से दूध, दही एवं पनीर, कमलेश कुमरावत, अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड नमकीन सागर कुटी चौराहा पीथमपुर से मावा बर्फी, मावा रोल एवं नमकीन तथा पदम श्री स्वीट्स एवं नमकीन सागर कुटी चौराहा पीथमपुर से मावा बर्फी, मावा पेड़ा एवं नमकीन के नमूने जाँच हेतु लिए। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष खेड़कर के द्वारा गंधवानी स्थित विभिन्न मिठाई नमकीन एवं अन्य दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कैलाश राठौड़ शिव रेस्टोरेंट जिराबाद से मावा बर्फी, श्री खाटू श्याम राजस्थान मिष्ठान भंडार बस स्टैंड गंधवानी से मलाई बर्फी, श्री महेश मालवीय मां भगवती उपहार गृह सिनेमा चौक गंधवानी से पेड़, कालिया धनगर शुभम दूध डेयरी बस स्टैंड गंधवानी से मिल्क केक, सुनील चौधरी श्री कृष्णा दूध डेरी बस स्टैंड गंधवानी से मावा पेड़ा, संतोष सोलंकी बालाजी दूध डेरी सिंघाना रोड से मिश्रित दूध एवं योगेश ठाकुर बालाजी चार्ट सेंटर एवं स्वीट सिंघाना से मावा एवं पनीर के नमूने जांच हेतु लिए गए। मंगलवार को मनावर में निरीक्षण एवं नमूना कार्रवाई की गई, जिसमें दिनेश चौधरी कृष्णा दूध डेरी से मिश्रित दूध, मुकेश शर्मा बागेश्वरी मिष्ठान भंडार से मावा, मावा बर्फी एवं मिल्क केक, पुरुषोत्तम शर्मा तृप्ति स्वीट्स मनावर से मलाई बर्फी मिल्क केक एवं मावा, देवेंद्र शर्मा अन्नपूर्णा नमकीन स्वीट्स मनावर से बूंदी लड्डू, पेड़ा, मिल्क केक, ओम सिंह राजपुरोहित राजस्थान स्वीट्स और नमकीन मनावर से नमकीन एवं मावा के नमूने जांच हेतु लिए गए। आर. जी. माऊटा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा ग्राम अहमद तहसील सरदारपुर स्थित अन्नपूर्णा नमकीन से रतलामी नमकीन एवं सेंधा नमक तथा न्यू महावीर नमकीन राजगढ़ तहसील सरदारपुर से नमकीन सेव का नमूना जांच हेतु लिया गया। जिला धार अंतर्गत खाद्य सुरक्षा प्रशासन के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने निरंतर कार्रवाई करते हुए अब तक लगभग 100 नमूने से ऊपर जांच हेतु लिए गए हैं।

आंगनवाड़ी भवन पर बालिका पोषण माह मनाया

माही की गूंज, करवड़।

महिला बाल विकास विभाग ने अंतरराष्ट्रीय बालिका पोषण माह के अवसर पर पाटीदार मोहल्ले के आंगनवाड़ी भवन पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया । कार्यक्रम की शुरुआत छोटी-छोटी बेटियों को चंदा पाटीदार के द्वारा तिलक लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की, यह कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है तो कल है योजना के तहत हुई मंगलवार को छोटी-छोटी बालिकाओं का जन्म दिवस आंगनवाड़ी भवन पर मनाया गया एवं खिलौने गिफ्ट किए गए इस आयोजन में महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी पेटलावद अजय तिवारी पर्यवेक्षक शीला हरवाल, ने रंगोली बनाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। इस आयोजन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूजा शर्मा चंदा पाटीदार ,गायत्री सिनम ,पुष्पा मालवीय ,शीला गामड़ ,संतोष भूरिया, बबीता खरीवाल ने छोटी-छोटी बालिकाओं के साथ जन्मदिवस मनाया कार्यक्रम में उपस्थित आंगनवाड़ी सहायिका आशा मोरवाल, रेशम डामर, ललिता बामनिया उपस्थिति रही।

स्वास्थ्य विभाग खेलः रातो रात बाले-बाले हो गई भर्ती, सोशल मीडिया पर उठ रहे सवाल

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

जिले के पेटलावद सहित सभी विकास खंडों में आउट सोर्स कर्मचारियों की भर्ती हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी झाबुआ द्वारा पत्र जारी करने के बाद प्रत्येक उप स्वास्थ केंद्र पर एक व्यक्ति की भर्ती की गई और ये भर्ती अब विवादों में आ गई है। क्योंकि उक्त भर्ती के संबंध में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई ओर पेटलावद सहित लगभग सभी विकासखंडों में ज्यादातर जगहों पर भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया ओर लेने देन कर सेटिंग से भर्ती कर दी गई । मामला उजागर होने के बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर पोस्ट सार्वजनिक हुई तो पूरा खेल सामने आया है। अब स्वास्थ विभाग मामले से पल्ला झाड़ते हुए भर्ती प्रक्रिया के लिए निजी एजेंसी को जिम्मेदार बता रही है।

पेटलावद में हुई 70 स्थानों पर हुई भर्ती

पेटलावद विकास खंड में स्वास्थ्य विभाग में कुल 70 लोगों की नियुक्ति के आदेश जारी हुवे है। भर्ती को लेकर कोई विज्ञप्ति जारी नहीं हुई ओर नियुक्ति के लिए एक से डेढ़ लाख रुपए प्रति व्यक्ति की लेन देन की जानकारी सामने आ रही है । ग्राम कचरौटिया उप स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती हेतु बद्रीलाल गामड़ द्वारा आवेदन किया गया था साथ ही रायपुरिया क्षेत्र में पदस्थ एक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी द्वारा युवक से भर्ती हेतु लेन देन की गई लेकिन भर्ती किसी ओर की गई। भर्ती नहीं होने पर बिचौलिए द्वारा भर्ती हुए युवक की भर्ती निरस्त कर युवक की भर्ती देने का आश्वासन दिया जा रहा है। बीएमओ एम एल चौपड़ा ने इस विषय में बताया कि भर्ती का काम सेडमैप वालो द्वारा की गई है ,रायपुरिया क्षेत्र में इस प्रकार की कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है ,यदि ऐसा कुछ हुआ हैं तो जानकारी लेता हु। वैसे तो विभाग में हुई भर्ती की जानकारी ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों को हैं लेकिन निजी एजेंसी के नाम पर जिम्मेदार अपनी भूमिका होने से बचने का प्रयास कर रहे है।

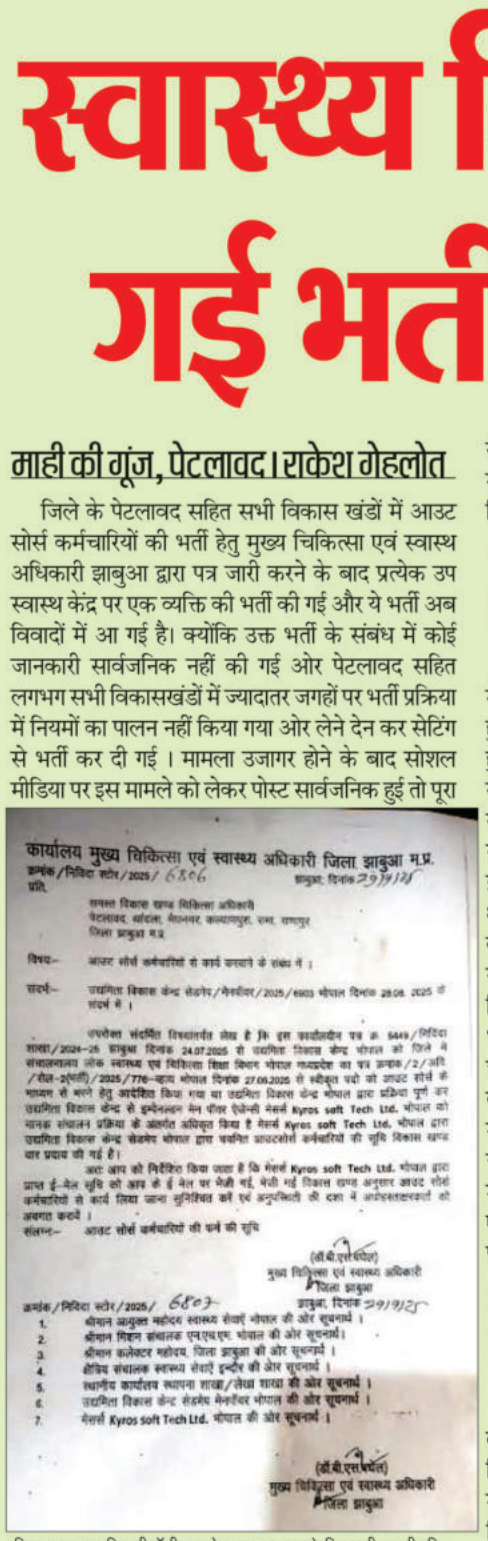

जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बीएस बघेल द्वारा अवकाश के दिन जारी पत्र की प्रति।

आखिर छुट्टी के दिन क्यों हुआ आदेश जारी , जिला स्वास्थ्य अधिकारी संदेह के घेरे में

भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक पत्र माही की गूंज के हाथ लगा है जो पेटलावद विकास खंड में हुई 70 कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ भेजा गया। उक्त पत्र स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झाबुआ द्वारा जारी किया गया जिसका पत्र क्रमांक/निविदा स्टोर/2052/6806 झाबुआ दिनांक 29.09.2025 को जारी किया गया जिसके तहत आउट सोर्स कर्मचारियों को कार्य करवाने के संबंध में सभी ब्लाकों में भेजा गया। उक्त पत्र के अनुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक 5459/निविदा शाखा/2024-25 झाबुआ दिनांक 24.07.2025 से उद्यमिता विकास केंद्र भोपाल को जिले में संचनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक/2/अवि /सेल2(भर्ती)/2025/776-व्हाया भोपाल दिनांक 27.06.2025 से स्वीकृत पदों को आउट सोर्स के माध्यम से भरने हेतु आदेशित किया था उद्यमिता विकास केंद्र भोपाल द्वारा प्रक्रिया पूर्ण कर उद्यमिता विकास केंद्र से इंपेनलडन मेन पावर एजेंसी मैसर्स क्योरस सॉफ्ट टच लिमिटेड भोपाल को अधिकृत किया गया था । जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी एस बघेल द्वारा जारी आदेश अनुसार मैसर्स क्योरस सॉफ्ट टच लिमिटेड भोपाल द्वारा प्राप्त ई मेल की सूची को सभी विकास खंडों को नियुक्त कर्मचारियों की सूची भेजी गई है सूची अनुसार पदस्थ कर्मचारियों से कार्य लेना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए। सबसे बड़ी बात इस आदेश को 29 सितंबर को जारी किया गया ओर उस दिन महाअष्टमी की सरकारी छुट्टी घोषित थी । छुट्टी के दिन ताबड़तोड़ आदेश जारी कर कर्मचारियों की भर्ती सुनिश्चित करना कही न कही विभाग की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है।

सोशल मीडिया पर फर्जी ढंग से हुई भर्ती को लेकर उठी आवाज ,जांच ओर कार्रवाई की मांग।

एक पद एक आवेदन

भर्ती प्रक्रिया में हुई हेराफेरी की यदि जांच की जाए तो पता चलेगा कि केवल पेटलावद विकास खंड में ही नहीं बल्कि अन्य विकास खंड में भी भर्ती के लिए ज्यादातर पदों पर केवल एक ही आवेदन प्राप्त किया गया जो कि बिना किसी लेन देन ओर आपसी तालमेल के संभव नहीं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी की भूमिका पूरे मामले में संदिग्ध नजर आ रही है जो बिना जांच पड़ताल के मैसर्स क्योरस सॉफ्ट टच लिमिटेड भोपाल उपलब्ध सूची को मान्य कर भर्ती में हुई नियुक्ति के लिए छुट्टी आदेश जारी कर रहे है। विभाग के जिम्मेदार अधिकारी सीधे इस भर्ती में शामिल नहीं ये साफ है लेकिन भर्ती जिम्मेदार अधिकारियों की जानकारी में नहीं हुई ये बात कही मानने में भी नहीं आती है।

लाखों की लेन देन के लग रहे आरोप

मामले के उजागर होते ही कई युवा जो इस पद से वंचित रह गए ओर पद पाने के लिए लेन देन करने के बाद भी नौकरी नहीं पा सके वो कही न कही इस भर्ती घोटाले के बहार आने के मुख्य कारण रहे । भर्ती के लिए दी गई राशि अटकने ओर अभी भी नौकरी मिलने की उम्मीद के चलते खुल कर सामने नहीं आ रहे है पर जानकारी सार्वजनिक होने के बाद सोशल मीडिया पर सूची सहित लेन देन के आरोप ओर फर्जी भर्ती को लेकर पोस्ट वायरल हो रही है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप से लगातार घिर रही प्रदेश सरकार के सामने एक ओर बड़ी चुनौती है क्योंकि पेटलावद सहित जिले भर में हुई भर्ती में अगर लेन देन के आंकड़े को माना जाए तो मामला करोड़ो की लेन देन तक जा रहा है। जिसकी जांच होनी चाहिए जिस एजेंसी को भर्ती का कार्य सोपा गया उसकी भी जांच होनी चाहिए आखिर उक्त एजेंसी के तार कहा कहा ओर किस किस से जुड़े है।

हाथ कंगन को आरसी क्या...

मामलाः तीन माह के बाद भी सामान्य नकल की प्रमाणित प्रति नहीं देने का

14/07/2025 को नकल की प्रमाणित प्रति का आवेदन पर प्रमाणित प्रति नही देने पर जनसुनवाई व सीएम हेल्पलाईन पर शिकायत।

माही की गूंज, झाबुआ।

जिस बात को हम सामान्य व छोटी समझते हैं वह बात कई बार बड़ी होती है पर हम उसका एहसास नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसा ही एक सामान्य कार्रवाई का मामला है। जिसकी नकल मांगने पर कलेक्टर के अधीन लोक सेवा अधिकारी तीन माह से गुमराह कर नकल देने से बच रहा है और कलेक्टर की भी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास एक प्रमाणित नकल नहीं देकर कर रहा है।

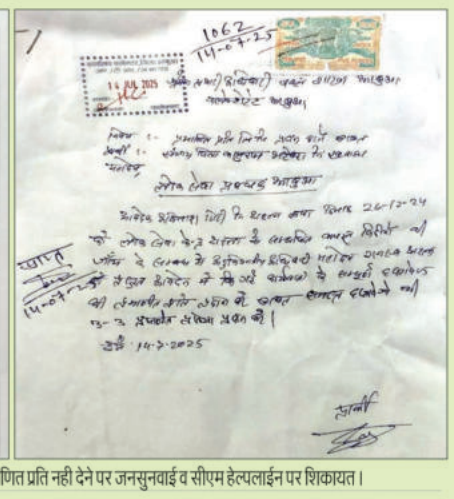

मामला है थांदला के लोक सेवा केंद्र पर आधार सेंटर का, जहां आधार त्रुटि सुधार व आधार बनाने पर निर्धारित राशि से अधिक राशि अवैध रूप से वसूली जा रही थी। जिसकी जनहित में एक युवक ने मय वीडियो के साथ लिखित शिकायत थांदला अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) को की गई थी। शिकायत दिनांक 26 दिसंबर 2024 को ही मामले को गंभीरता से लेकर तात्कालिक एसडीएम तरुण जैन ने मामले को संज्ञान में लिया। और शिकायत दिनांक के दिन ही लोक सेवा केंद्र थांदला का श्री जैन ने निरीक्षण किया। तथा आधार कार्ड सेंटर पर कार्यरत शिवम कुमार गुप्ता एवं अभिषेक कुमार गुप्ता समक्ष में उपस्थित होकर कथन अंकित किये तथा वीडियो का अवलोकन भी किया। जिसमें एसडीएम द्वारा पुष्टि की गई कि, लोक सेवा केंद्र के संचालक विनय कुमार गुप्ता के निर्देशन पर आधार सेंटर लोक सेवा केंद्र थांदला में निर्धारित शुल्क से अधिक की अवैध राशि मांगी जा रही है जो अनुचित है। तथा विनय कुमार गुप्ता के उक्त कृत्य से शासन की छवि धूमिल हो रही है के लेखन के साथ तात्कालिक एसडीएम श्री जैन ने विनय कुमार गुप्ता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु कलेक्टर (ई -गवर्नेंस) झाबुआ को प्रतिवेदन क्रमांक / रीडर -2/2024/ 2803 प्रेषित किया। एसडीएम के उक्त प्रतिवेदन के साथ संलग्न शिवकुमार गुप्ता, अभिषेक कुमार गुप्ता के कथन व वीडियो भी प्रेषित किये।

जनहित में 14 जुलाई 2025 को एसडीएम के उक्त प्रतिवेदन के साथ की गई समस्त कार्रवाई के प्रमाणित प्रतिवेदन की नकल संजय भटेवरा द्वारा झाबुआ कलेक्टेऊट नकल शाखा से मांगी गई। जब 14 जुलाई 2025 को उक्त संबंधित मामले की प्रमाणित नकल मांगी गई थी उस समय तो यही था कि, उक्त मामले की नकल सामान्य ही है और कलेक्टर नकल शाखा झाबुआ आवेदन दिनांक को ही आवेदक को इस नकल की प्रमाणित प्रति दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पूरे उक्त सामान्य मामले को बड़ा व रहस्यमयी मामला बनाने का प्रयास झाबुआ कलेक्ट्रेट में कई बार चक्कर लगाने के बाद भी कुछदिन - कुछदिन कहकर लोक सेवा के प्रबंधक संत कुमार चौबे ने किया।

बात यहां यह कि, एक सामान्य कार्रवाई की नकल की प्रमाणित प्रति नहीं देना और उक्त मामले को रहस्यमयी व बड़ा होने का संदेह संत कुमार चौबे ने उत्पन्न किया है। जिसमें यह कि, चौबे साहब पहले कहते हैं कि, इस मामले से मेरा लेना-देना व मेरे अधिकार में नहीं है। उक्त नकल की प्रतिलिपि ई-गर्वनेंस के प्रबंधक राजू बिलवाल देंगे कह कर गुमराह करते रहे। वहीं जब ई- गर्वनेंस के प्रबंधक श्री बिलवाल से बात होने पर बिना गोलमोल के सीधा व सही बात कही कि, एसडीएम थांदला द्वारा कलेक्टर ई-गर्वनेंस के नाम से विनय गुप्ता के विरोध कठोर कार्रवाई करने हेतु एसडीएम थांदला का प्रतिवेदन मय कथन के साथ हमारे कार्यालय आया था। परंतु यह मामला लोक सेवा केंद्र से संबंधित था, इसलिये कार्रवाई हेतु लोक सेवा केंद्र के प्रबंधक को एसडीएम द्वारा जारी प्रतिवेदन प्रेषित कर दिया था। जब आवेदक ने कहा कि, बिलवाल जी, चौबे जी ने हमें पिछली बार कहा कि, मेरा कह देना बिलवाल जी आपको यह नकल दे देंगे। तत्पश्चात श्री बिलवाल ने हमारे सामने ही अपने कार्यालय से ही संत कुमार चौबे को फोन किया और कहा कि, चौबे जी आवेदक, थांदला एसडीएम के 26 दिसंबर 2024 प्रतिवेदन वाले मामले की प्रमाणित नकल मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि, चौबे जी, ने कहा बिलवाल जी दे देंगे। क्या मैं, यह नकल इन आवेदक को दे दूं...? तो चौबे जी ने फोन पर कहा मैं अभी भोपाल हूं अभी आप नकल मत दो। कह कर कहा कि, मैं कलेक्टर से बात करूगां उसके बाद देखते है। और बिलवाल जी ने चौबे जी के मना करने पर नकल नहीं दी व चौबे जी से हुई बात बताई।

अब यहां यह है कि, एक सामान्य नकल की प्रमाणित प्रति नहीं देकर आवेदक को गुमराह करने के साथ कलेक्टर का बार-बार नाम लेकर कलेक्टर की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास भी चौबे द्वारा किया जा रहा है। और चौबे जी अपने आप को ही सही साबित करने में लगे हैं। अगर हाथ कंगन को आरसी क्या...? यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर चौबे जी, विनय गुप्ता की अवैध वसूली में कोई हाथ यानी संरक्षण नहीं है तो पिछले तीन माह से आवेदक को गुमराह नहीं करते। और न ही कलेक्टर का नाम लेकर बेवजह कलेक्टर की प्रतिष्ठा को भी खराब नहीं करते हुए उक्त मामले की नकल दे दी जाती। लेकिन उक्त छोटे मामले को संदेह युक्त बनाकर इस मामले का रुख किसी बड़े मामले से जुड़ा है ऐसा प्रतीत चौबे जी के कृत्यों से पता चलता है। और यह अंदाजा लगाना गलत नहीं होगा कि, उक्त साहब के संरक्षण से ही शायद विनय गुप्ता, आपरेटर के माध्यम से ही लोक सेवा आधार सेंटर पर अवैध वसूली का खेल कर रहा होगा और अवैध वसूली में से उसका हिस्सा शायद उक्त साहब की जब तक भी जा रहा होगा। इसीलिये एक सामान्य कार्रवाई की प्रमाणित नकल कलेक्टर मैडम जिनका नकल देने न देने में कोई हस्तक्षेप नहीं है लेकिन चौबे साहब, उनके नाम का दुरुपयोग कर कलेक्टर मैडम की प्रतिष्ठा को भी खराब करने का घिनौना कृत्य किया जा रहा है।

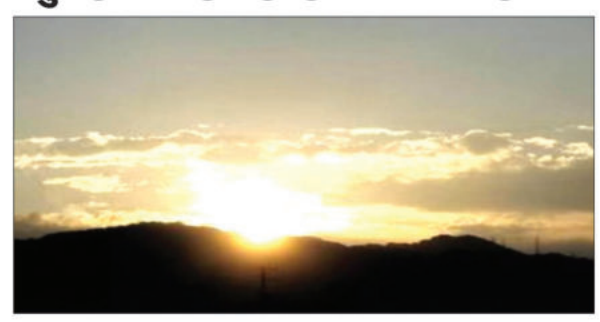

नतीजन प्रमाणित नकल नहीं देने का यह मामला अब कलेक्टर जनसुनवाई से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक पहुंच गया है। और मंगलवार को भी आवेदक को गुमराह करने का प्रयास किया। अब आगे पता चलेगा कि, सीएम हेल्पलाइन, कलेक्टर जिला पंचायत सीईओ तक नकल का पहुंचे इस मामले में चौबे जी अब अपनी कौन सी जादूगरी दिखाते हैं...? या मामले को सामान्य मानकर यह नकल की प्रामाणिक प्रति देते हैं।

सुबह शाम हो रहा है ठण्ड का एहसास

माही की गूंज, खवासा।

मानसून के बाद अब मौसम में बदलाव महसूस किया जा रहा है। रात में हल्की ठण्ड का एहसास होने लगा है जबकि दिन में धूप और गर्मी का एहसास बरकरार है। लोगों ने बताया कि इस समय का मौसम ना तो पूरी तरह से गर्म है, ना ही ठण्डा। बल्कि सुबह-शाम ठंडक और दिन में हल्की गर्मी का मिश्रण है। मौसम जानकारी के अनुसार मानसून के जाने के बाद हवा में नमी की मात्रा कम होने लगी है। जिससे सुबह और रात के समय ठंडी हवा चलने लगी है। दिन में हल्की गर्मी और रात की ठंडक का यह मौसम स्वास्थ्य और जीवनशैली दोनों के लिए अनुकूल नही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन के लिए यह स्थिति बनी रहने का अनुमान जताया है। वही हल्की ठंडक का एहसास रहेगा। जबकि दिन में तेज धूप से गर्मी महसूस हो सकती है।

दिल्ली व भोपाल शिक्षक सम्मेलन में जाने हेतु बनाई भुमिका

माही की गूंज, खवासा।

मंगलवार को आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्यप्रदेश जिला झाबुआ के ब्लाक थांदला के कुल चार संकुल केंद्रों बालक खवासा , कन्या खवासा ,कुकड़ीपाड़ा एवं चापानेर संकुलों की सामूहिक बैठक रखी गई। उक्त बैठक कृषि उपज मंडी खवासा में हुई, बैठक में 9 नवंबर को पुरानी पेंशन बहाली रैली के लिए दिल्ली चलने एवं भोपाल महासम्मेलन को लेकर भुमिका बनाई व चर्चा की। बैठक को प्रांतीय संगठन मंत्री जवानसिंह बारिया ने संबोधित किया एवं चारों संकुल के शिक्षकों की समस्याओं ओर सुझावों को सुना ।

उपस्थित नवीन शिक्षक संवर्ग के साथियों ने दोनों कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सहमति प्रदान की एवं सभी ने अपनी-अपनी सुविधा अनुसार सूची बनाकर वाहन बुक करवाने के लिए राशि जमा करी। इस अवसर पर जिला सह सचिव मंशाराम गरवाल एवं आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के ब्लाक अध्यक्ष मिठूसिंह गणावा, ब्लाक उपाध्यक्ष पीसी पाटीदार ने भी अध्यापकों को संबोधित किया।

बैठक में चारों संकुल अध्यक्ष बालक खवासा से किशोर पाटीदार, कन्या खवासा से दिलीप डोडियार , चापानेर से गंगाराम भूरिया , नाथूसिंह डामोर सहित शिक्षक साथी उपस्थित रहें।

जाहिर सुचना

यह कि, मेरे पक्षकारगण कृष्णा पिता श्याम सोलंकी, रविना पिता श्याम सोलंकी, मेघा पिता श्याम सोलंकी व श्रीमती कमलादेवी पति श्याम सोलंकी पेटलावद के रहवासी होकर ग्राम रूपगढ पटवारी हल्का नम्बर 44 तहसील पेटलावद में पैत्रक कृषि भूमि अर्थात नारायण पिता आयदान जी सोलंकी के समय की कृषि भूमि चली आई हैं। जिसकें वर्तमान खाता कमांक 449 सर्वे नम्बर 614/2/1/2.615/1/2, 616 कुल रकबा 1.18 है। कुल लगान 4.55 पेसे की कृषि भूमि राजस्व अभिलेख मे दर्ज है। जिस पर मेरे पक्षकार कृष्णा और कमलादेवी काश्त करते है। यह कि मेरे पक्षकारगण के पिता/पति पूर्व में करीब 10 बिघा कृषि भूमि को बिकी कर चुके है। शेष भूमि जों बची है वह मेरे पक्षकारगण कें वैध आधिपत्य की होकर मेरे पक्षकारगण पैत्रक भूमि के वैध वारीसगण हैं। मेरे पक्षकारगण के आधिपत्य व हिस्सें वाली उक्त भूमि को श्याम सोलंकी कों बिक्री, अंतरण, सौदा करने का कोई भी अधिकार नही आता है। इसकें बावजूद कोई भी पक्ष मेरे पक्षकारगण कें बालें बाल इस भूमि का सौदा, अंतरण, खरीदी, बिक्री करेगा तों वह मेरे पक्षकारगण पर बंधनकारक नही होकर अवैध व शुन्य होगी। अतः मेरे पक्षकारगण की ओर सें जाहिर सुचना का प्रकाशन किया जाता है सो सही है।

इति दिनांक - 10.10.2025

एडवोकेट
दीपक कुमार बैरागी
मोबाइल नंबर - 9406681475

किराए के फार्मासिस्ट के भरोसे जारी दवा दुकानों के लाइसेंस, नियमों का पालन ही नहीं करवाते ड्रग इंस्पेक्टर

जहरीले कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद जागी सरकार

माही की गूंज , पेटलावद।

झाबुआ जिले के अधिकतर मेडिकल स्टोर्स पर फार्मासिस्ट नही है जिसका कारण स्वास्थ्य विभाग व औषधि निरीक्षक की मिली भगत से जिले भर में अवैध किराए के लाइसेंस पर नोसिखिया मेडिकल संचालित कर रहे। पेटलावद विकासखंड में ज्यादातर मेडिकल संचालकों के पास फार्मासिस्ट उपलब्ध नहीं है और अन सीखे पढ़ाए युवा, आमजन की स्वास्थ व्यवस्था को संभाल कर दवाई देने का काम कर रहे है। यह स्वास्थ्य विभाग व औषधि निरीक्षक की अनदेखी मानी जा रही हैं। जिसके कारण जिलेभर में किराए के लाइसेंस पर अवैध मेडिकल संचालित धड़ल्ले से हो रहे है। जो कि शासन प्रशासन के निर्देश अनुसार मेडिकल पर फार्मासिस्ट का रहना अनिवार्य होता है। मगर ऐसा नही होना मतलब स्वास्थ्य विभाग व ओषधि निरीक्षक की मेडिकल संचालकों से तगड़ी साठगांठ होगी जिसके कारण जिलेभर में अवैध किराए के मेडिकल लाइसेंस पर अधिकतर मेडिकल संचालित हो रहे है।

सजा का प्रावधान पर सेटिंग के चलते किसी को खौफ नहीं

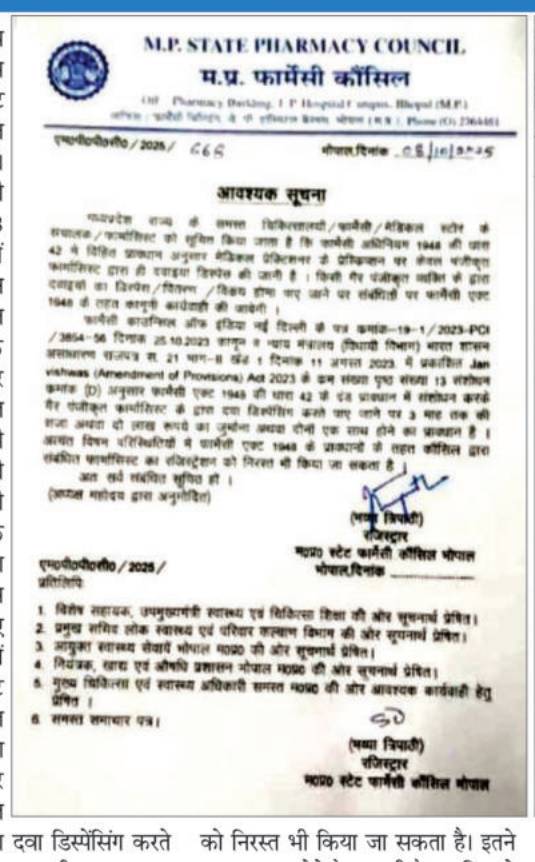

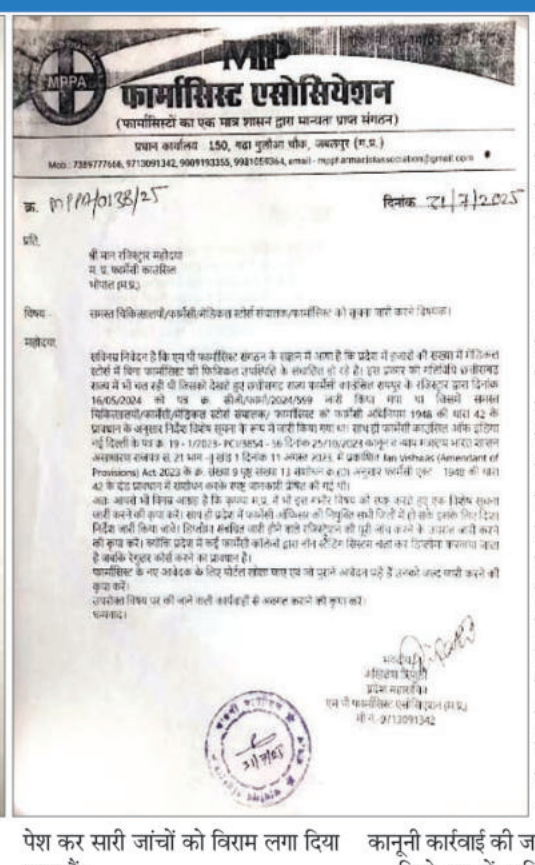

अधिकतर मेडिकल संचालकों द्वारा बिना फार्मासिस्ट के मेडिकल संचालित किए जा रहे है। यह स्वास्थ्य विभाग में बैठे बड़े अधिकारी व औषधि निरीक्षक की मेहरबानी से अवेध किराए के लाइसेंस व बिना फार्मासिस्ट के मेडिकल संचालित हो रहे है। जो कि फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 42 में विहित प्रावधान अनुसार मेडिकल प्रेक्टिशनर के प्रेस्किप्शन पर केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट द्वारा ही दवाइयां डिस्पेंस की जानी चाहिए। किसी गैर पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा दवाइयों का डिस्पेंस, वितरण व विक्रय होना पाए जाने पर संबंधितों पर फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। गैर पंजीकृत फार्मासिस्ट के द्वारा दवा डिस्पेंसिंग करते पाए जाने पर 3 माह तक की सजा अथवा दो लाख रूपए का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है। एसे में फार्मेसी एक्ट 1948 के प्रावधानों के तहत कौंसिल द्वारा संबंधित फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन को निरस्त भी किया जा सकता है। इतने सख्त कानून होने के बाद भी केवल दिखावे के लिए क्षेत्र में संचालित मेडिकलो के नाम मात्र जांच होती है। यहां तक बताया जा रहा है कि, ज्यादातर दुकानदारों की राशि फीक्स है जांचकर्ता अधिकारी के आते ही लिफाफा पेश कर सारी जांचों को विराम लगा दिया जाता हैं।

M.P. STATE PHARMACY COUNCIL
म.प्र. फार्मेसी कौंसिल

आवश्यक सूचना

1. विशेष सहायक, उपमुख्यमंत्री स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त म0प्र0 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त समाचार पत्र।

(भव्या त्रिपाठी)
रजिस्ट्रार
म0प्र0 स्टेट फार्मेसी कौंसिल भोपाल

फार्मासिस्ट एसोसियेशन

शासन ने जारी किए आदेश

म.प्र. फार्मेसी कौंसिल भोपाल 8 अक्टूबर को मेडिकल संचालकों को आवश्यक सूचना निर्देश किए। जिसमें मध्यप्रदेश राज्य के समस्त चिकित्सालयों, फार्मेसी, मेडिकल स्टोर के संचालक, फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 42 में विहित प्रावधान अनुसार मेडिकल प्रेक्टिशनर के प्रेस्किप्शन पर केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट द्वारा ही दवाइयां डिस्पेंस की जानी चाहिए। किसी गैर पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा दवाइयों का डिस्पेंस, वितरण, विक्रय होना पाए जाने पर संबंधितों पर फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाना बताया है।

जिले भर में अधिकाशं गैर-पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दवा वितरण बिक्री की जा रही हैं।वही जिलेभर में अधिकतर अवैध पंजीकृत मेडिकल संचालित हो रहे जिसके जिम्मेदार जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है और ड्रग इंस्पेक्टर है जिनको समय समय पर मेडिकल स्टोर की जांच करनी होती है।

लापरवाही हुई तो लाइसेंस निरस्त होगा

मध्यप्रदेश काउंसिल ने सभी फार्मेसी संचालकों से अपील की है कि, वे नियमों का पालन करें और जनता को सुरक्षित एवं प्रमाणित फार्मास्यूटिकल सेवाएं प्रदान करें। म.प्र. स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा जारी अधिसूचना का सभी प्रदेश के फार्मासिस्ट से दवा वितरण व्यवसाईयों से आग्रह किया है कि, आम जनता के स्वास्थ हित में यह सार्थक प्रयास सफल हुआ है। कृपया सभी आदेश का पालन करें। संगठन के प्रदेश सहसचिव एड़ी. बच्चन ने कहा कि, यह आम जनता के स्वास्थ हित में सम्मानजनक निर्णय हुआ है। अब इस निर्णय पर मेडिकल संचालक कितना अमल करते है ये समय बताएगा। फिलहाल सरकार द्वारा जारी नए निर्देश के बाद कई मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई होनी थी जो देखने को नहीं मिली। प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से हुई 25 से ज्यादा बच्चों की मौत के सरकार कड़े कदम उठाने के दावे कर रही है। पर जमीनी स्तर पर अधिकारी की मिलीभगत के चलते कई प्रकार की अमानक जीवन रक्षक दवाइयां आमजन के जीवन से खिलवाड़ करते हुए खुले आम बिक रही है।

संपादकीय

बीमार भविष्य की नींव

यह आंकड़ा हमारे शिक्षा तंत्र की विफलता को दर्शाता है कि एक लाख से अधिक स्कूलों की पढ़ाई सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रही है। एक स्कूल की सारी कक्षाओं को एक शिक्षक कैसे पढ़ाता होगा? छात्र-छात्राएं कैसी और कितनी शिक्षा ग्रहण कर पाते होंगे, अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। शिक्षा मंत्रालय के हालिया आंकड़े बताते हैं कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में एक लाख चार हजार स्कूल ऐसे थे, जो केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। इन स्कूलों में करीब पौने चौंतीस लाख विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या सबसे ज्यादा थी, जबकि उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और लक्षद्वीप का स्थान है। एक तो हमारे देश में शिक्षा का बजट पहले ही बहुत कम है, फिर उस धन का सही उपयोग नहीं हो पाता। इसमें दो राय नहीं कि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के गिरते स्तर के मूल में हमारे नीति-नियंताओं की अनदेखी ही प्रमुख कारक है। आखिर हम अपने नौनिहालों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं? आखिर उनके बेहतर भविष्य की हम कैसे उम्मीद करें? जाहिर बात है कि एक शिक्षक सामाजिक विषय, भाषा, विज्ञान, अंग्रेजी और गणित में माहिर नहीं हो सकता। एक शिक्षक छात्रों की हाजिरी दर्ज करेगा या पढ़ाई कराएगा? शिक्षा का मतलब छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। उन्हें पढ़ाई के साथ पाठ्यसहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान दिया जाना जरूरी होता है। लेकिन जब स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक ही नहीं होंगे तो किताबी पढ़ाई कैसी होगी, अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही महत्वपूर्ण नहीं होती। बच्चों का शारीरिक विकास पूरी तरह हो, उसके लिए खेल, पीटी और योग जैसी कक्षाओं की सख्त जरूरत होती है। लेकिन जब शिक्षक ही पर्याप्त नहीं होंगे तो शिक्षा के साथ चलने वाली गतिविधियों की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। निस्संदेह, हम छात्रों के बीमार भविष्य की बुनियाद ही रख रहे हैं।

सही मायनों में स्कूलों का शिक्षकों की कमी से जूझना शिक्षा विभाग की नाकामी को ही दर्शाता है। यह हमारे सत्ताधीशों की संवेदनहीनता का भी पर्याय है। शिक्षकों की नियुक्ति में जिस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामले विभिन्न राज्यों में सामने आए हैं, उससे शिक्षा विभाग की प्रदूषित कार्य संस्कृति का बोध होता है। आखिर क्या वजह है कि देश में प्रशिक्षित शिक्षकों की पर्याप्त संख्या होने के बावजूद स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। यह स्थिति हमारे तंत्र की विफलता को ही उजागर करती है। एक समस्या यह भी है कि शिक्षक जटिल भौगोलिक स्थितियों वाले स्कूलों में काम करने से कतराते हैं। यदि इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हो भी जाती है तो वे दुर्गम से सुगम स्कूलों में अपना तबादला ज्वाइन करने के तुरंत बाद करवा लेते हैं। जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप से लेकर विभागीय लेन-देन की भी शिकायत होती रहती है। यही वजह है कि शहरों व आसपास के इलाकों में स्थित स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती जरूरत से ज्यादा भी देखी जाती है। कैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सड़कों पर बेरोजगारों की लाइन लगी हैं और स्कूलों में शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं। बताया जाता है कि माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालयों में करीब साढ़े आठ लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके बावजूद कि हमारे यहां प्रशिक्षित शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। कहने को तो हमारे गाल बजाते नेता भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं का देश कहते इतराते हैं, लेकिन इन नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि कुंठित होती युवा पीढ़ी के लिये उन्होंने क्या खास किया है? नौकरियों की भर्ती निकलती नहीं है। निकलती है तो पेपर आउट होने की खबरें आती हैं। सालों-साल उनके परिणाम नहीं निकलते। यदि परिणाम निकले भी तो फिर धांधली के आरोप लगने लग जाते हैं। फिर मामला वर्षों तक अदालतों में डोलता रहता है। विडंबना यह भी है कि आज सरकारी स्कूलों में गरीब व कमजोर वर्गों के बच्चे ज्यादा भर्ती होते हैं, इसलिए इन स्कूलों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। यदि सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के बच्चों के लिये इन स्कूलों में पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए तो स्थिति बदल जाएगी।

तालिबान को सैन्य मदद की आशंका से सहमा पाक

पाक-अफ़ग़ान युद्ध ऐसे ही नहीं रुका है। उसका सबसे बड़ा कारण भारत रहा है। दावेदारी सऊदी अरब, यूएई और ईरान की तरफ़ से हो रही है कि उनके समझाने-बुझाने पर दोनों पक्ष मान गए हैं। इस तथाकथित शांति रथ के चौथे सवार, राष्ट्रपति ट्रम्प भी हो गए हैं। ट्रम्प ने बयान दिया, 'मैं तो शांति कराने में माहिर, 'पीस एक्सपर्ट' हूं। भारत-पाक को टैरिफ की धमकी दी, वो मान गए।' अब कोई पूछे, अफ़ग़ान अमीरात ट्रम्प की टैरिफ धमकी को गंभीरता से लेगा क्या? उनके पास खोने के लिए है क्या? ख़ैर, इस हंसी-मज़ाक़ से अलग, जो कुछ पाकिस्तानी प्रिंट मीडिया ने अपने सत्ता प्रतिष्ठान को समझाया है, वो बिलकुल 'कन्विंसिंग' और निशाने पर था।

भारत क्यों कारण रहा, इसे समझने के लिए पाकिस्तान से प्रकाशित दो अख़बारों के सम्पादकीय को पढ़ लेना काफी होगा। 'अफ़ग़ान क्लैशेज़' शीर्षक से द डॉन सम्पादकीय लिखता है, 'पाकिस्तान को इस बात से भी सावधान रहना चाहिए कि भारत और अफ़ग़ान तालिबान, जो कभी कट्टर दुश्मन थे, के बीच अचानक संबंधों में गर्मजोशी आ गई है, और हाल ही में अफ़ग़ान विदेशमंत्री का नई दिल्ली में सौहार्दपूर्ण स्वागत किया गया। इसलिए, काबुल के साथ संबंधों को, चाहे कितने भी तनावपूर्ण क्यों न हों, और बिगड़ने देना इस देश के हित में नहीं होगा।'

'दिल्ली-काबुल पैचअप' शीर्षक से एक्सप्रेस ट्रिब्यून का सम्पादकीय है, 'चूंकि पाकिस्तान ने हमेशा अपने शत्रुओं के प्रति, चाहे वह भारत हो या अफगानिस्तान, शांति का हाथ बढ़ाया है। आपसी सम्मान और सौहार्द के आधार पर संबंध बनाने की कोशिश की है, इसलिए अब समय आ गया है कि कूटनीति को एक और मौका दिया जाए। अफगान तालिबान अधिकारियों के साथ बातचीत की जाए, ताकि आतंकवाद से निपटने में सहयोग किया जा सके तथा संबंधों में शांति सुनिश्चित की जा सके।'

भारत में मुत्ताक़ी के भव्य स्वागत को लेकर पाकिस्तान के सीने पर सांप लोट रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का एक हिस्सा गुरुवार को काबुल में की गयी सर्जिकल स्ट्राइक को पाकिस्तान की बेवकूफाना हरकत मान रहा है। डॉन ने लीपापोती करते हुए लिखा, 'फ़िलहाल, शत्रुता समाप्त हो गई है। और अब इस मामले को और बिगड़ने से रोकना चाहिए। हालांकि अतीत में छोटे स्तर की झड़पें हुई, लेकिन हाल के वर्षों में यह सबसे बड़ी झड़प है।'

तालिबान शासन ने 85 पाकिस्तानी सैनिकों-अफसरों को ढेर किये जाने का दावा किया है। जबकि पाक सेना के जनरल केवल 23 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार कर रहे हैं। सबसे मुश्किल में सियासतदां फंसे हैं। 'खुद मियां फ़ज़ीहत' जनता को जवाब कैसे दें? राष्ट्रपति ज़रदारी ने 'भारत द्वारा प्रायोजित' आतंकवाद के खतरे को 'क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा ख़तरा' बताया। राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान की हालिया 'उकसावे वाली कार्रवाइयों' की कड़ी निंदा की, और दोहराया कि पाकिस्तान राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेगा।

दरअसल, इन्हें भारत का डर सताने लगा है कि इस बार डुरंड लाइन पर कोई 'ग्रेट गेम' दिल्ली की तरफ से न हो जाये। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2,640 किमी लंबी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है। यह रेखा पश्तून जनजातीय क्षेत्र से होकर दक्षिण में बलोचिस्तान से बीच से होकर गुजरती है। ये दोनों इलाके आतंकग्रस्त हैं, जहां कबीलाई क्षत्रपों की चलती है। पाकिस्तान के कॉलमनिस्ट शहीद जावेद बुर्की कहते हैं, 'वाशिंगटन और इस्लामाबाद, दोनों ही इस्लामिक स्टेट-खोरासन और टीटीपी जैसे आतंकी समूहों को नियंत्रण में लाने में काबुल की मदद चाहते हैं।'

अफ़ग़ानिस्तान की आर्थिक नाकेबंदी अब भी अमेरिका ने कर रखी है। अफ़ग़ानिस्तान के केंद्रीय बैंक के अरबों डॉलर की डिपॉज़िट पर अमेरिका जिस तरह कुंडली मारे बैठा है, उससे इस देश की बैंकिंग प्रणाली चरमरा रही है। अमेरिका की आंखें अफ़ग़ान ज़मीन के नीचे छिपे दुर्लभ खनिजों पर गड़ी हैं। दुनिया मानती है कि अफ़ग़ानिस्तान में समृद्ध खनिज संसाधनों के भंडार हैं, जो कई मूल्यवान उत्पादों जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, विमान, मिसाइल, चिकित्सा उपकरण, घरेलू उपकरण और अन्य उच्च-मूल्य वाले उत्पादों के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक हैं।

पेंटागन ने बहुत पहले उसका सर्वे करा लिया था, जब मित्र सेनाएं तैनात थीं। माना जाता है कि यह खरबों डॉलर में है। दुर्लभ खनिजों से भरा क्षेत्र कज़ाकिस्तान से शुरू होकर अफ़ग़ानिस्तान- पाकिस्तान के कबायली इलाकों में समाप्त होता है। चीन की उपस्थिति भी इसी वजह से है। और इन सबों को डर भारत से है, कि यदि दिल्ली ने अफ़ग़ानिस्तान में इस बार सही से डेरा जमा लिया, तो फिर दुर्लभ खनिजों की बंदरबांट सहजता से नहीं हो पायेगी।

इस बार पाकिस्तान के खिलाफ अफ़ग़ान पब्लिक भी सड़क पर उतर आई है। उसकी वजह शरणार्थी हैं। करीब 18 लाख से ज़्यादा अफ़ग़ान शरणार्थी आर्थिक मंदी और कठोर प्रतिबंधों की वजह से देश लौटने को मजबूर हुए हैं। सबसे भयावह तस्वीरें ईरान और पाकिस्तान से वापस भगाये गए अफ़ग़ान शरणार्थियों की है। इसलिए, पाकिस्तान के जो लोग मुस्लिम एकता की बात करते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, क्या भय और ग़रबत से भागे अफ़ग़ान शरणार्थी मुसलमान नहीं थे? केवल एक साल में पाकिस्तान से 3,52,000 अफ़ग़ान शरणार्थी भगाये गए हैं। पाक अधिकारियों ने उन्हें अस्थायी शरणार्थी कार्ड देना बंद कर दिया। जिनके वीज़ा समाप्त हो गए, उन लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी तेज़ कर दी।

पुष्परंजन

आज जब लगा, कि तालिबान नेतृत्व युद्ध की स्थिति में भारत से मदद ले सकता है, तो 'मुस्लिम सॉलिडरिटी' का अनहद नाद आरम्भ हो गया।

बाहर देखने पर यह लग रहा है, कि अफ़ग़ानिस्तान-भारत के बीच आर्थिक और मानवीय सहयोग के हवाले से कूटनीति हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के रणनीतिकार इसकी पड़ताल में लगे हैं कि नई दिल्ली, काबुल को इंटेलिजेंस शेयरिंग से लेकर सैन्य साज़ो-सामान की मदद तो नहीं कर रहा है? 12 मार्च, 2013 को तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी ने संसद को जानकारी दी थी, कि 4 अक्तूबर, 2011 को अफ़ग़ानिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौता (एसपीए) हुआ था, जो दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग का प्रावधान करता है। 'एसपीए' के अंतर्गत भारत, अफ़ग़ान राष्ट्रीय सुरक्षाबलों के प्रशिक्षण, उपकरण और सैन्य क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में सहायता करने का संकल्प लिया गया था। इसकी धाराओं में स्पष्ट है कि रक्षा क्षेत्र में भारत की सहायता अफ़ग़ानिस्तान सरकार के विशिष्ट अनुरोधों पर आधारित होगी।' वह रणनीतिक समझौता हामिद करज़ई की मौजूदगी में नई दिल्ली में हुआ था। रावलपिंडी की नींद 'एसपीए' की वैधता को लेकर उड़ी हुई है, जिसे आधार बनाकर मुत्ताक़ी भारत से सैन्य मदद मांग सकते हैं।

तालिबानी बंदिशों के बीच सिसकती स्त्री अस्मिता

पिछले दिनों अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत यात्रा पर आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर उसमें महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया गया। जब इस बात की आलोचना हुई तो उन्होंने एक बचकाना बहाना बनाया कि एंट्री पास की कमी के कारण ऐसा किया गया। खैर, बाद में एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई, जिसमें महिला पत्रकारों को बुलाया गया। उन्होंने परेशान करने वाले सवाल भी पूछे। इसे महिला पत्रकारों की कामयाबी ही कहा जाएगा कि वे अपने इस प्रयास में सफल हुईं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां स्त्री-पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।

जब से तालिबान दोबारा सत्ता में आए हैं, उन्होंने पहले की तरह ही महिलाओं पर तरह-तरह की बंदिशें लगाई हैं। वहां का महिला कल्याण मंत्रालय खत्म कर दिया गया है। कोई महिला या बच्ची अगर बिना मुंह ढके दिखे, तो उसे कठोर दंड भी दिया जा सकता है। वे न पढ़ सकती हैं, न लिख सकती हैं। छठी कक्षा से आगे वे पढ़ नहीं सकतीं। पुरुष अध्यापक उन्हें पढ़ा नहीं सकते। अफगानिस्तान दुनिया का एकमात्र देश है, जहां स्त्रियों के पढ़ने पर प्रतिबंध है। वे विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं ले सकतीं। एक बार मार्च, 2022 में लड़कियों के स्कूल को तालिबानों ने खोला था, लेकिन खोलने के कुछ घंटों बाद ही बंद कर दिया गया। लड़कियां किसी कैम्पस में न वीडियो बना सकती हैं, न अपने फोटो खींच सकती हैं।

तालिबानों के सत्ता में आने से पहले अफगानिस्तान में सत्ताईस प्रतिशत स्त्रियां नौकरी करती थीं। लेकिन अब उनका भविष्य अंधकारमय है। यही नहीं, कई प्रांतों में दुकानदारों को आदेश दिए गए हैं कि यदि कोई स्त्री बिना किसी पुरुष रिश्तेदार के साथ आए, तो उसे सामान न दिया जाए। वे किसी जिम में भी बिना किसी पुरुष रिश्तेदार के नहीं जा सकतीं।

नौ साल की उम्र में लड़कियों की शादी जायज है। वे कृषि, सिविल इंजीनियरिंग, पत्रकारिता आदि नहीं पढ़ सकतीं क्योंकि नेताओं के अनुसार ये विषय महिलाओं के लिए बहुत कठिन हैं। महिलाएं किसी टीवी प्रोग्राम में भाग नहीं ले सकतीं। वे न किसी फिल्म में काम कर सकती हैं। बहुत से संस्थानों में उनके नौकरी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। महिलाएं खिड़की से बाहर न झांकें, इसलिए यदि उनके घर में ऐसी खिड़कियां हैं, तो उन्हें बंद करना पड़ा है। महिलाओं को चेहरा ढकना तो अनिवार्य है ही। कारण कि महिलाओं को देखकर पुरुष लालायित न हों। कमाल है न, यदि कोई पुरुष किसी महिला को वासना भरी नजरों से देख रहा है, तो उसमें भी पुरुष का नहीं महिला का ही दोष हुआ। उनका इलाज भी सिर्फ महिला डाक्टर ही कर सकती हैं।

कोई बताए कि जब महिलाएं पढ़ेंगी-लिखेंगी ही नहीं, तो डाक्टर कैसे बनेंगी। महिला डाक्टर नहीं होंगी, तो महिलाओं को इलाज भी नहीं मिलेगा। वे मरती हैं, तो मरती रहें। वे किसी पुरुष रिश्तेदार के बिना कहीं जा-आ नहीं सकतीं। यही नहीं, यह आदेश भी है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, वे घर से बाहर न निकलें। उन्हें जोर से बोलना नहीं है। हंसना भी नहीं है। किसी पुरुष को उनकी हंसी सुनाई नहीं देनी चाहिए। वे संगीत भी नहीं सुन सकतीं। गा भी नहीं सकतीं। पिछले दिनों अफगानिस्तान में कुछ महिलाएं मलबे के नीचे दबी हुई थीं। बचाव दल वहां पहुंचा भी। लेकिन महिलाओं को नहीं बचाया गया, क्योंकि पुरुष महिलाओं को नहीं छू सकते थे।

आखिर ये कैसी सोच है। लेकिन कोई करे भी तो क्या। विरोध के स्वर अपनों के ही बीच से निकलते हैं। बाहर का कोई किसी समाज को नहीं बदल सकता। रूस और अमेरिका ने ऐसा करके देख लिया है। उन्हें वहां से भागना ही पड़ा। एक तरफ सऊदी अरब में महिलाओं को बहुत-सी बातों से मुक्ति दी जा रही है। जबकि सऊदी अरब में भी महिलाओं के लिए बहुत से कठोर कानून रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान में स्त्रियों का कोई मददगार नहीं। अधिकांश अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भी चुप्पी साध रखी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जरूर एक बार बयान दिया था। जो लोग ब्यूटी पेजेंटस को ही असली स्त्री अधिकार समझते हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि धरती के इसी भाग में महिलाएं कितनी मुसीबतों का सामना कर रही हैं। उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। भारत में जरूर एक महिला पत्रकार ने साहस के साथ तालिबानी मंत्री से इस बारे में सवाल पूछा।

जो साधन-सम्पन्न स्त्रियां थीं, वे अफगानिस्तान से पहले ही जा चुकी हैं। हमेशा ऐसा ही तो होता है। साधन-सम्पन्न हर मुसीबत से बचने की राह खोज लेते हैं। अब वहां वे स्त्रियां रह गई हैं, जो सरकार के रहमोकरम पर ही जिंदा रह सकती हैं। रहमोकरम भी कैसा, जहां लगभग सांस लेने पर भी बंदिश है। स्त्रियां जाएं तो जाएं कहां।

क्षमा शर्मा

दरअसल, इन दिनों देशों को अपने व्यापारिक हित पहले नजर आते हैं, स्त्रियों के मानवाधिकार बाद में। तभी तो बहुत से ऐसे देश जो साम्यवादी विचार की वकालत करते हैं, उन्होंने बिना समय गंवाए तालिबानों का समर्थन किया।

तालिबान जब पहले सत्ता में आए थे, तब भी उन्होंने स्त्रियों पर किस कदर कहर ढाया था, इस पर अफगानिस्तान की ही सारा शाह ने चुपके-चुपके एक फिल्म बनाई थी- बिहाइंड द वेल। इसमें एक दृश्य में एक बड़े स्टेडियम में बंदूक धारी खड़े हैं। बहुत से दर्शक भी मौजूद हैं। वह सफेद बुर्के में लिपटी एक स्त्री लाई जाती है। उसके पीछे दूसरी स्त्री है। पहली स्त्री को जमीन पर बिठा दिया जाता है। फिर उसे गोली मारी जाती है। वह ढेर हो जाती है। फिर दूसरी स्त्री उसके दिल पर हाथ रखकर बताती है कि हां, वह सचमुच मर चुकी है। स्त्रियों को इस तरह से मारने से शायद धर्म की रक्षा हो जाती होगी।

सच बात तो यह है कि जो सत्ताएं भी धर्म से चलती हैं, उन्हें किसी बड़े से बड़े अपराधी को सजा देने की इतनी जल्दी नहीं पड़ी रहती, जितनी कि स्त्रियों को। स्त्रियां डरें, तभी तो काबू में रहेंगी। लेकिन अगर पीछे का सच देखेंगे, तो इन सत्ताओं को स्त्रियों से बहुत डर लगता है। तभी उन पर दाब-धौंस वाले ऐसे कानून लागू किए जाते हैं, जिन्हें धर्म का मुलम्मा पहनाकर, उसकी रक्षा की बात की जाती है। अगर सचमुच स्त्रियों से इतनी नफरत है तो क्यों उनसे विवाह करते हो, क्यों उनसे संतान उत्पन्न की जाती हैं।

क्षेत्र में खुलेआम कच्ची शराब का व्यापार जोरों पर

माही की गूंज, शाजापुर।
अजय राज केवट

अकोदिया नगर में जोर-शोर से कच्ची शराब बिक रही है। कुछ मोहल्ले तो कच्ची शराब के नाम से जाने जाते हैं। जैसे रेलवे पटरी पार रेलवे फाटक के पास सुंदरसी बस स्टैंड चौराहा, जाटपुरा संजय कॉलोनी, अकोदिया गांव, फूलने कोलिया चपाड़िया ऐसी बहुत सी जगह चिन्हित कर रखी है। कच्ची शराब के लिए वहां जब पहुंचोगे जब आपको कच्ची शराब उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि आबकारी विभाग इस मामले को नजरअंदाज करके चल रहे हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले पटरी पार कच्ची शराब बेचने वाले को आबकारी अधिकारी ने पुलिस की भाषा में समझाइए देकर छोड़ दिया, लेकिन कच्ची शराब बेचने वाले के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनको आबकारी विभाग का कोई डर नहीं। कच्ची शराब पीने से कितने ही लोगों की रेलवे प्लेटफार्म पर मौत हो चुकी है, क्योंकि सुनसान इलाका वही है जहां पर कच्ची शराब लेकर आदमी वही पीकर सो जाता है या फिर कुछ लोग कच्ची शराब पीकर मार्केट में धूम मचाते हैं मोबाइल चुराते हैं चोरियां करते हैं। क्योंकि उनको तो रोज कच्ची शराब पीने के लिए पैसा चाहिए इसलिए चोरी भी करेंगे मोबाइल भी चुराएंगे लूट मार भी करेंगे।

जाटपुरा के मोहल्ले वालों ने बताया कि, हमारे मोहल्ले में तो दूध की डेरी जिस हिसाब से चलती है उस हिसाब से कच्ची शराब की डेरी चल रही है। मोहल्ले वाले इतने परेशान होकर बताते है कि, कच्ची शराब पीकर उसी मोहल्ले में लोग अपने नशे की धूम मचाते हैं। कितनी ही बार तो वहां पर इस मामले को लेकर मारपीट भी हो गई, लेकिन प्रशासन कच्ची शराब पर पाबंदी क्यों नहीं लग रहे हैं। क्या आबकारी अधिकारी वहां भी अपना ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे...? कुछ कच्ची शराब बेचने वाले किसी जनप्रतिनिधि आबकारी एवं पुलिस प्रशासन से अपने अच्छे संबंध को वाला देकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

कच्ची शराब का नशा इतना चल रहा है कि लाइसेंस की शराब भी अपनी लिमिट के अंदर बिकना बंद हो गई है क्योंकि वहां पर 80 रुपए में क्वार्टर मिलता है एवं कच्ची शराब बेचने वाले के यहां 30 रुपए में ही नशा आ जाता है। फिर ठेके पर 80 रुपए का क्वार्टर क्यों लेने जाएंगे, जब हर गली मोहल्ले में ही 30 रुपए में शराब मिल रही है। तो अब देखना यह है कि, आबकारी विभाग कच्ची शराब को लेकर अपनी नींद से जागेंगे या नहीं...?

काले हिरण और नीलगाय पकड़ने का अनोखा अभियान शुरू

माही की गूंज, शाजापुर।

मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे काले हिरण और नीलगाय अब सरकार के निशाने पर हैं। इन जानवरों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने एक बड़ा और अनोखा अभियान शुरू किया है।

इस काम में मदद के लिए दक्षिण अफ्रीका से विशेषज्ञों की 15 सदस्यीय टीम 15 अक्टूबर को भोपाल पहुंचे गई और शाजापुर जिले के कालापीपल से अभियान की शुरुआत करेगी।

इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वन विभाग ने रॉबिन्सन हेलिकॉप्टर किराए पर लिया है। हेलिकॉप्टर से हांका लगाकर (जानवरों को घेरकर) उन्हें पकड़ा जाएगा। यह अभियान 15 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक चलेगा। पहले चरण में कालापीपल और शुजालपुर क्षेत्र को चुना गया है, जिसमें इमलीखेड़ा, भानियाखेड़ी, डुंगलाय, उमरसिंघी और अरनिया काला जैसे गांव शामिल हैं।

पकड़े गए काले हिरण और नीलगाय को विशेष वाहनों से मंदसौर जिले की गांधी सागर सेंचुरी में शिफ्ट किया जाएगा। वन विभाग के पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अधिकारियों का कहना है कि अगर यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा, तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

भाजपा विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने किसानों की समस्या को मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने कई बार उठाया था। इसके बाद सरकार ने इस अभियान को मंजूरी दी। अब विधायक ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे इस अभियान में सहयोग करें। जिन क्षेत्रों में हिरण और नीलगाय झुंड में दिखें, उसकी जानकारी तुरंत रेस्क्यू टीम या गांव के सरपंच को दें ताकि टीम सही समय पर पहुंचकर कार्रवाई कर सके।

सरपंचों को इस काम की जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे गांव वालों से संपर्क में रहें और वन विभाग को सही लोकेशन की जानकारी दें। यह अभियान न सिर्फ किसानों को राहत देगा बल्कि वन्यजीवों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में भी मददगार साबित होगा।

आरएसएस ने अनुशासन और उत्साह के साथ निकाला पथ संचलन

माही की गूंज, अकोदिया।

संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय कृषि उपज मंडी परिसर में हुआ। यहां पवित्र भगवा ध्वज को प्रणाम किया गया, जिसके बाद शारीरिक प्रदर्शन और शस्त्र पूजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्वयंसेवकों ने शारीरिक व्यायाम और योगाभ्यास भी किया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि बद्रीलाल पुष्पक और हरि सिंह परमार उपस्थित रहे। सह-कार्यवाह सोनू चौहान भी मौजूद थे। समारोह के मुख्य वक्ता विभाग प्रचारक राम लोधी ने संघ की 100 वर्ष की यात्रा पर प्रकाश डाला और 'पंच परिवर्तन' के तहत पांच कार्यों को करने का आह्वान किया।

पथ संचलन कृषि उपज मंडी प्रांगण से शुरू हुआ और नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरा। इसमें बस स्टैंड, शुजालपुर रोड, परशुराम चौराहा, अहिंसा द्वार, टप्पा चौराहा, हनुमान मंदिर चौराहा, वैध गली, अन्नपूर्णा माता मंदिर, जाटपुरा, बोलाई रोड, सिद्धि विनायक चौराहा, झंडा चौक, शिवाजी मार्केट, सब्जी बाजार, स्टेट बैंक रोड, झीन कॉलोनी और सारंगपुर रोड शामिल थे। संचलन वापस मंडी परिसर पहुंचकर समाप्त हुआ।

पूरे नगर में आम नागरिकों, गणमान्य व्यक्तियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने स्वयंसेवकों का भव्य स्वागत किया। कई स्थानों पर जेसीबी मशीनों से पुष्प वर्षा की गई और प्रमुख चौराहों पर फूलों की बारिश कर अभिनंदन किया गया। प्रत्येक वार्ड में महिलाओं ने रंगोली बनाकर संचलन का स्वागत किया। घोष दल संचलन का मुख्य आकर्षण रहा, जिसकी ताल पर स्वयंसेवक कदमताल करते हुए आगे बढ़ रहे थे।

सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाना पुलिस के साथ-साथ जिले के अन्य पुलिस थानों का पुलिस बल भी तैनात किया गया था। पुलिस ने पूरे संचलन की ड्रोन कैमरों से निगरानी की, जिससे शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित हो सका।

शर्मनाक हरकत, एबीवीपी के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले के भानपुरा स्थित शासकीय कॉलेज में छात्राओं के साथ एक शर्मनाक घटना घटित हुई है। यहां युवा उत्सव के दौरान एबीवीपी के नगर मंत्री सहित कुछ छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने कपड़े बदल रही छात्राओं के फोटो वीडियो बनाए।

इस मामले में छात्राओं ने प्राचार्य को शिकायत की। जिसके बाद पुलिस ने तीन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक छात्र अभी भी फरार है। युवकों द्वारा छात्राओं के फोटो वीडियो बनाने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

खिड़की से वीडिया बनाने का अरोप

मंगलवार को भानपुरा में स्थित शासकीय महाविद्यालय में चल रहे युवा उत्सव में एबीवीपी के नगर मंत्री सहित एबीवीपी के दो अन्य कार्यकर्ताओं पर कपड़े बदल रही छात्राओं के फोटो वीडियो बनाने के आरोप लगे है। बताया जा रहा है कि, ये लोग कपड़े बदल रही छात्राओं के कॉलेज के कक्ष क्रमांक 10 की उजालदानी में से अपने मोबाइल में फोटो और वीडियो बना रहे थे। इसकी भनक जब छात्राओं को लगी तो उन्होंने इसकी शिकायत प्रभारी प्राचार्य को की। महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य ने मामले में सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए। जिसमें युवकों द्वारा की जा रही संदिग्ध हरकते कैद हुई।

तीन आरोपी गिरफ्तार

सामने आए सीसीटीवी फुटेज में यह दिखाई दे रहा है कि, एक युवक दूसरे युवक के कंधे पर खड़ा होकर मोबाइल से वीडियो फोटो लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद प्रभारी प्राचार्य ने भानपुरा पुलिस को लिखित शिकायत की। जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुए छात्रों में एबीवीपी के नगर मंत्री उमेश जोशी, सह महाविद्यालय प्रमुख अजय गौड और एक कार्यकर्ता हिमांशु बैरागी शामिल है। जबकि एक अन्य कार्यकर्ता फिलहाल फरार है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर पुलिस ने शांति भंग करने की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उपजेल गरोठ भेज दिया गया है।

वर्षा ऋतु के बाद शिवना नदी को स्वच्छ बनाने में जुटे शिवना योद्धा

माही की गूंज, मंदसौर।

शिवना शुद्धिकरण अभियान के तहत नदी की व्यापक सफाई का कार्य किया गया। वर्षा ऋतु के बाद नदी में जमा हुई गाद,प्लास्टिक, कचरे को निकाल कर नदी को पुनः स्वच्छ स्वरूप देने का प्रयास किया गया। इस श्रमदान में आम नागरिकों, समाजसेवियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

इस अवसर पर विधायक विपिन जेन ने कहा कि, वर्षा ऋतु के बाद नदी में बहकर आने वाला कचरा जल को प्रदूषित कर देता है,इसलिए नियमित सफाई बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिवना केवल एक नदी नहीं बल्कि मंदसौर की जीवन रेखा है, इसे स्वच्छ रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। अभियान के दौरान श्रमदानियों ने नदी किनारे फैले कचरे को हटाया और नागरिकों को जागरूक करते हुए अपील की कि कोई भी व्यक्ति नदी में कचरा, मूर्तियां या पूजन सामग्री न डाले। वैसे इस शिवना नदी प्रदूषण मुक्त अभियान में हर आयु वर्ग के लोग इसमें भाग ले रहे हे और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं।

जिला आयुष अधिकारी ने किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्रों का निरीक्षण

माही की गूंज, मंदसौर। जिला आयुष अधिकारी डॉ. बिंदु ध्रुव ने शासकीय आयुर्वेद औषधालय आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) बाजखेड़ी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एएमओ औषधालय प्रभारी डॉ. पंकज डाभी एवं सीएएमओ डॉ. सर्वेश जैन सहित सभी अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। सबसे पहले अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर डॉ. ध्रुव का आत्मीय स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान डॉ. ध्रुव ने औषधालय परिसर, योग कक्ष, हर्बल गार्डन, औषधि स्टॉक कक्ष, वितरण कक्ष एवं अधिकारी-कर्मचारी बैठक कक्ष का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने सभी शासकीय दस्तावेजों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश व सुझाव दिए। इस दौरान औषधालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने डॉ. बिंदु ध्रुव को औषधीय पौधा भेंट कर आभार व्यक्त किया। डॉ. ध्रुव ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर ढाबला एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर भगोर का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

हृदय गति रुकने से अजीत जैन का निधन

माही की गूंज, शाजापुर।

नगर के समाजसेवी लोकप्रिय हर एक धार्मिक कार्य मिलनसार सबके दिल पर राज करने वाले हर धार्मिक कार्य में सेवा देने वाले राजेश जैन, विनोद जैन के छोटे भाई अजीत जैन का हृदय गति रूकने से उनका निधन हो गया। उन्होंने इतना भी समय नहीं दिया कि कोई उन्हें समझ सके कि क्या हुआ है। सुबह उठकर रोज की तरह अपनी दुकान पर पहुंचे दुकान खोलकर दुकान पर पोहे बनाए एवं सभी को सुबह-सुबह चाय नाश्ता भी करवाया। उसके बाद वह दुकान पर महेश को बोले कि, मैं अभी आता हूं। दुकान से घर के लिए निकले एवं पथ संचलन के लिए ड्रेस पहनकर पथ संचलन में जाने के लिए अपने घर वापस आए। तनोडिया से अजीत के सासू-ससुर पत्नी संध्या जैन का हाथ फैक्चर होने के कारण समाचार लेने अकोदिया आए थे। सुबह 9 बजे घर में ही घर के दरवाजे के यहां चक्कर आने से गिर गए। उन्हें तुरंत उपचार के लिए सुजालपुर जश हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ जांच करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बस फिर क्या था 30 मिनट में ही पूरे नगर में शोक की लहर फैल गई पूरे नगर में सन्नाटा छा गया। हर एक की जुबान पर एक ही नाम था अजीत भाई हमें छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन प्रभु को यह मंजूर नहीं था और प्रभु अजीत को अपने पास ले गए। राष्ट्र सेवक संघ का पथ संचलन अकोदिया नगर में निकलना था उसके पहले अपने हाथों से बनाकर अजीत ने सभी को पोहे खिलाकर जो पूर्ण कमाया है वह किसी से छुपा हुआ नहीं। अजीत के अंतिम संस्कार में हर एक घर से लोग निकल कर अंतिम संस्कार में पहुंचे मुक्तिधाम में जब वहां शोक संदेश चल रहे थे तब वहां नगर के हर एक व्यक्ति की आंख में आंसू दिखाई दे रहे थे। जैन के अंतिम संस्कार में इतने लोग शामिल हुए हैं जैसे अकोदिया के मुक्तिधाम में कोई मेला लगा है।

अब तुलसी और ज्यादा असरदार

माही की गूंज, मंदसौर।

भारत में धार्मिक और औषधीय महत्व रखने वाली तुलसी अब और अधिक प्रभावशाली रूप में सामने आई है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर के विज्ञानियों ने अखिल भारतीय औषधि एवं सगंध परियोजना के तहत तुलसी की एक नई किस्म तैयार की है 'राज विजय बेसिल-16'।

यह किस्म तुलसी के ओसीमम बेसिलिकम वर्ग से विकसित की गई है। विज्ञानियों का दावा है कि इसमें चार गुना ज्यादा औषधीय गुण और तेल की मात्रा अधिक है, जो इसे औषधीय उपयोग के लिहाज से बेहद खास बनाता है।

मंदसौर अनुसंधान केंद्र के विज्ञानी डा.आरएस चूड़ावत, डॉ. बीके कचौली और डा. बीके पाटीदार द्वारा चार साल के परिश्रम के बाद विकसित की ग तुलसी की यह नई किस्म 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी बीज उपज 22.41 किलो प्रति हेक्टेयर और तेल की मात्रा 67.49 किलो प्रति हेक्टेयर है।

यह कीट प्रतिरोधी होने के कारण इसमें कीटनाशकों की लागत नहीं आती, जिससे किसानों को ज्यादा लाभ होता है। इस किस्म के बीज में ओमेगा-तीन और फैटी एसिड का समृद्ध स्त्रोत है। यह शरीर की गर्मी को कम करती है और रक्त शर्करा को नियंत्रित करती है। इसके साथ ही कृषि विज्ञानी ने बताया कि इसके अर्क से आइसक्रीम भी बनाई जा सकेगी।

फैक्ट फाइल

औषधीय गुण : तुलसी की अन्य किस्सों से 4 गुना ज्यादा
तेल : 67.49 किलो प्रति हेक्टेयर
बीज उत्पादन : 22.41 किलो प्रति हेक्टेयर
फसल अवधि : 115-120 दिन
कीट प्रतिरोधी, कम लागत
सोयाबीन जैसी फसलों का विकल्प
देश की पहली आयल तुलसी वैरायटी

सोयाबीन की जगह ले सकती है ये तुलसी

मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में व्यावसायिक तौर पर पैदा की जाने वाली तुलसी पारंपरिक सोयाबीन की फसल का अच्छा विकल्प बन सकती है। कृषि विज्ञानियों का मानना है कि यह किस्म न केवल औषधीय दृष्टिकोण से बल्कि व्यावसायिक खेती के लिहाज से भी फायदेमंद है। इसकी उत्पादकता सोयाबीन जैसी पारंपरिक फसलों से अधिक है।

चार राज्यों की जलवायु में पूरी तरह अनुकूल

इस तुलसी की खेती मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तरप्रदेश में की जा सकती है। क्योंकि शोध में यह किस्म इन राज्यों की जलवायु के अनुकुल पाई गई है।

पारंपरिक तुलसी की तुलना में बेहतर उपज और कीटों से भी सुरक्षा

तुलसी की एक नई उन्नत किस्म ÷राज विजय बेसिल-16 पारंपरिक तुलसी की तुलना में उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिहाज से काफी बेहतर मानी जा रही है। पारंपरिक तुलसी औसतन पांच किलो प्रति हेक्टेयर तक उपज देती है। इसके पकने की अवधि 110-115 दिन है। साथ ही सामान्य तुलसी में कीट लगने की संभावना अधिक होती है, जबकि राज विजय बेसिल-16 में प्रतिरोधक क्षमता बेहतर पाई गई है।

वजन घटाने से लेकर हाई कैलोरी फूड तक, कई फायदे एक साथ

तुलसी की नई किस्म 'राज विजय बेसिल-16' सिर्फ खेती के नजरिए से ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और आहार के क्षेत्र में भी बेहद उपयोगी साबित होगी। इस किस्म का उपयोग अब हाई कैलोरी फूड में भी किया जा सकेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक इसे भीगो कर खाने से भूख नहीं लगती, जिससे यह वजन नियंत्रित करने में सहायक है। इसके अलावा यह शरीर में कोलेस्ट्राल को कम करने में भी मदद करती है। यही वजह है कि इसे अब फालूदा जैसे हेल्दी डिंक्स में भी मिलाया जा सकेगा। नई किस्म न सिर्फ किसानों को अधिक उत्पादन देगी, बल्कि फूड इंडस्ट्री के लिए भी एक नई संभावना बनकर उभरेगी।

विश्वविद्यालय के मंदसौर महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र के विज्ञानियों द्वारा तैयार की गई तुलसी की किस्म में तुलसी की अन्य किस्मों के मुकाबले कई गुना ज्यादा औषधीय गुण हैं। इसकी वजह से यह वैराइटी खास मानी जा रही है। इसे तैयार करने में तीन से चार साल लगे हैं। जल्द ही यह किसानों के लिए उपलब्ध होगी।

तारीख पर तारीख आखिर कब तक...

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की 600 जोड़ों की राशि का नही हुआ भुगतान, जनसुनवाई में मिला नया आश्वासन

माही की गूंज, झाबुआ।

मंगलवार को जन सुनवाई कार्यक्रम में जिले पेटलावद और राणपुर ब्लॉक के नव विवाहित शादीशुदा जोड़े मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के बाद शासन द्वारा दी जाने वाली राशि से वंचित है। लगातार हितग्राहीयो द्वारा ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को आवेदन निवेदन कर राशि की मांग कर रहे है लेकिन विगत सात माह से इनके हिस्से केवल आश्वासन ही आया है और इस बार जिला कलेक्टर द्वारा नए आश्वासन के साथ योजना के हितग्राहियों को खाली हाथ लौटा दिया गया। अब हितग्राही बहन और उनके साथ आए उनके पति भी कहने लगे कि तारीख पर तारीख आखिर कब तक?

जनसुनवाई में पहुंचे जोड़े

मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में वर-वधु, जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में शामिल हुए थे, सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर आवेदन देने पहुंचे। आवेदन में बताया कि, 27 मार्च 2025 को जिला स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन, झाबुआ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत रानापुर ब्लॉक की 47 पचायतों से लगभग 292 वर-वधु और पेटलावद की सभी ग्राम पंचायतों से 320 वर वधु सम्मिलित हुए थे विवाह आयोजन के समय यह आश्वासन दिया गया था कि योंजना की प्रोत्साहन राशि शीघ्र ही सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। परंतु खेद का विषय है कि इतने ज्ञापन ओर जनसुनवाई में आवेदन देने के बाद आज दिनांक तक सात फेरे लिए हुए 7 माह से भी अधिक समय होने के बाद भी रानापुर ब्लॉक और पेटलावद ब्लॉक के हितग्राहियों के खातों में यह राशि जमा नहीं हुई है। जबकि झाबुआ जिले के अन्य ब्लॉकों तथा देश के अन्य जिलों में यह राशि समय पर प्रदाय कर दी गई है। हितग्राहीयों ने आवेदन में ये भी बताया गया कि जनपद सीईओ रानापुर ओर जनपद सीईओ पेटलावद को दो से तीन बार ओर जनसुनवाई में जिला सीओ झाबुआ के समक्ष भी निवेदन कर चुके हैं। इसके बाद भी भुगतान नहीं हुआ है।

आदिवासी समाज के साथ अन्याय का लगाया आरोप

आदिवासी संगठनों का आरोप है कि, आदिवासी कन्याओं को मिलने वाली राशि रोकी गई है। यह हमारे आदिवासी समाज के साथ घोर अन्याय एवं पक्षपात है और शासन-प्रशासन द्वारा उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। सरकार अभी लाडली बहनों के खातों में तो लगातार राशि डाल रही है उनके लिए बजट में रुपए है तो हमारे लिए क्यों नहीं इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है सभी हितग्राहियों को जल्द राशि का भुगतान किया जाए। राशि नहीं मिलने के कारण हितग्राही सहित उनका परिवार भी परेशान है और हितग्राहीयों को दूर दूर से खर्चा कर बार बार सरकारी कार्यालयों पर समय बर्बाद कर आना पड़ रहा है।

फिर मिला आश्वाशन ,मंत्री भूरिया के गृह जिले में भुगतान क्यों अटका

हर बार की तरह इस बार भी हितग्राहीयों की कलेक्टर की ओर से आश्वासन मिला जो पूर्व में अन्य अधिकारियों से मिलता रहा। हितग्राहियों ने बताया कि कलेक्टर मैडम ने राशि भुगतान के लिए एक माह का आश्वासन दिया है ऐसा पूर्व में दिए आवेदन पर भी 08दिन 15दिन ओर एक माह का आश्वासन मिलता रहा है। उधर मध्यप्रदेश शासन में जिले से केबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया के विधानसभा गृह क्षेत्र पेटलावद ओर भाजपा जिलाध्यक्ष भानू भूरिया के गृह क्षेत्र राणपुर ब्लॉक से कन्या विवाह के हितग्राहियों का भुगतान सात माह बाद भी नहीं होने पर इनकी कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं । वहीं सरकार ओर प्रशासन की ओर से लेट लतीफी पर लोग सवाल उठा रहे है आखिर दो ब्लॉक का भुगतान क्यों ओर किसने अटकाया ओर मंत्री होते भी भुगतान में देरी क्यों हो रही हैं।

इंदौर राजमार्ग पर किसानों का चक्काजाम

माही की गूंज, खंडवा।

किसानों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब मंडी में उन्हें मक्का का उचित मूल्य नहीं मिला। आक्रोशित किसानों ने बड़ी संख्या में मंडी के बाहर खंडवा-इंदौर राजमार्ग पर चक्काजाम कर दिया। इससे दोनों ओर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई और लंबा जाम लग गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लगभग तीन घंटे की बातचीत के बाद जाम खुलवाया गया।

किसानों ने बताया कि सुबह मक्का लेकर मंडी पहुंचे तो नीलामी की बोली मात्र 700 रुपये प्रति क्विंटल से शुरू की गई। उनका कहना है कि यह अन्याय है और व्यापारी मनमाने भाव तय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह समस्या केवल खंडवा मंडी में है, अन्य जगह उचित दाम मिल रहे हैं। किसानों ने मांग की कि मक्का की कीमत सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य 2200 रुपये प्रति क्विंटल के अनुरूप हो, मंडी में ही उपज खाली कराई जाए या परिवहन भाड़ा दिया जाए, मंडी के सभी तौल कांटे चालू किए जाएं, उपज का भुगतान तुरंत किया जाए और मंडी में अवैध वसूली बंद की जाए।

जाम के दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगीं। केवल एंबुलेंस को रास्ता दिया गया।

गोवंश तस्करी के आरोपी गिरफ्तार

माही की गूंज, खरगोन।

आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस ने मंगलवार को गोवंश तस्करी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। खलटाका पुलिस चौकी के जांच पॉइंट पर की गई कारवाई में एक टेम्पो से दो गोवंश मुक्त कराए गए, जिन्हें क्रूरतापूर्वक ले जाया जा रहा था।

पुलिस को मिली सूचना के आधार पर खलघाट की ओर आ रहे सफेद सुपर कैरी टेम्पो (एमपी46जेडई1518) को घेराबंदी कर रोका गया। वाहन में ले जाए जा रहे गोवंश संबंधी आरोपियों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान करण पिता विनायक भाबर और वाहन मालिक सागर पिता मोहन शिंदे के रूप में हुई। दोनों दावलेवेडी निवासी हैं। उनके खिलाफ मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिबंध अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने 20 हजार रुपए मूल्य के दो गोवंश को मुक्त कराया और तस्करी में प्रयुक्त 3 लाख रुपए मूल्य का टेम्पो जब्त कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

प्रेमिका का मोबाइल लेकर भागा युवक कुप में गिरा, हुई मौत

माही की गूंज, खंडवा।

इंदौर के एक युवक का शव खंडवा जिले के ग्राम पामाखेड़ी में कुप में पाया गया। परिजनों ने युवक की मौत को लेकर उसकी प्रेमिका और परिवार पर हत्या का आरोप लगाया। पोस्टमार्टम में पता चला कि युवक की मौत डूबने से हुई है। हालांकि पुलिस जांच और शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार यह एक्सीडेंटल घटना प्रतीत होती है। आशंका जताई जा रही है कि युवक खेत में भागते हुए कुएं में गिर गया।

इंदौर के डबल चौकी क्षेत्र रहने वाला 22 वर्षीय दीपक मानकर अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके गांव पहुंचा था बताया जा रहा है। प्रेमिका ने पुलिस को बताया कि दीपक बिना बताए उसके घर आया था। जब वह मोबाइल पर किसी अन्य युवक से बात कर रही थी, तब दीपक गुस्से में उसका मोबाइल छीनने लगा। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और दीपक भाग गया। वह खेत की तरफ भागते हुए कुप में गिर गया।

कुआं बिना मुंडेर का था और चारों तरफ ऊंची घास से घिरा हुआ था। कुएं की मिट्टी फिसलन भरी थी और पास कोई साथी नहीं था, इसलिए दीपक बाहर नहीं निकल पाया। नर्मदानगर टीआई विकास खिंची के अनुसार, कुएं से शव बरामद करने पर शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने मृतक की मौत डूबने से होने की पुष्टि की है। हालांकि, जांच के लिए कुछ अंगों के नमूने लिए गए हैं।

अवैध शराब जब्त

माही की गूंज, खरगोन।

ढापला क्षेत्र में अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान 84 हजार रुपये मूल्य की देशी-विदेशी शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई में एक महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। महिला का पति फरार है।

खरगोन वृत्त प्रभारी उप निरीक्षक मुकेश गोर ने बताया कि ठापला के खेड़ाफलिया में पुलिस की टीम ने तलाशी ली। पुलिस ने कालू पिता लडू दंगोड़ के मकान से 8 पेटी देशी मदिरा, 10 पेटी बियर और 4 टीन गोवा व्हिस्की बरामद की। कुल 22 पेटियों में 228 लीटर शराब जब्त की गई।

पुलिस ने मनूबाई पति कालू दंगोड़ के कब्जे से शराब जब्त की, जबकि महिला का पति कालू दंगोड़ सूचना मिलते ही मौके से फरार हो गया।

किसानों का सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन

माही की गूंज, बड़वानी।

पाही गांव में आदिवासी-दलित संगठन के नेतृत्व में आदिवासी किसानों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं और मांगों को रखा।

किसानों का कहना है कि, उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता। न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल कागजों तक सीमित है, जबकि कंपनियों को सस्ती बिजली, कर माफी और जमीन दी जा रही है। उदाहरण के तौर पर, विदेशी कपास पर कर माफी से कंपनियों को सस्ता कपास मिलता है, लेकिन किसानों को उनका सही भाव नहीं मिलता।

आदिवासी किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि, सरकार ने पिछले दस वर्षों में कंपनियों को एक लाख एकड़ से अधिक वन भूमि दे दी, जबकि वे सदियों से इन जमीनों पर खेती कर रहे हैं। किसान मांग कर रहे हैं कि बंदोबस्ती अभियान फिर से शुरू किया जाए, भूमि अभिलेख सुधारे जाएं और वन अधिकार कानून के तहत पात्र परिवारों को तत्काल अधिकार दिए जाएं।

फसल बीमा योजना भी किसानों के लिए लाभकारी नहीं है। वे मांग कर रहे हैं कि फसल नुकसान का मूल्यांकन सही तरीके से किया जाए और पिछले वर्षों की औसत उपज के आधार पर पूरा मुआवजा मिले।

किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं करती है, तो वे भोपाल तक सड़कों पर उतरेंगे।

संगठित समाज विरोधी विचारधारा को कर सकता है समाप्त

माही की गूंज, झाबुआ।

मध्यप्रदेश के आलीराजपुर जिले में अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, उसे बचाने के लिए सामाजिक स्तर पर लोगों ने सामुहिक प्रयास शुरु कर दिए है। यहां अनुठी पहल को प्रारंभ कर उन्होंने मतांतरण करने वालों के विरोध में अपने नियम तय किए और अपने मूल से दूर हो गए परिवारों को सूचित करते हुए समझाईश के साथ जागरुक भी किया। समाज में यह संदेश फैलाया कि, मतांतरित लोग जब हमारे मूल के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उन्हें कठोरता के साथ सामाजिक, धार्मिक, पारंपरिक पर्व, उत्सव, और त्यौहारों से अलग किया जाएगा। किसी भी प्रकार से मतांतरित परिवारो को सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

जनजातिय क्षेत्र में धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को लेकर नई चेतना उभरती हुई सामने दिखाई दे रही है। जनजाति क्षेत्र में स्थानिय ग्रामसभा संगठित होकर मतांतरण का खुलकर विरोध करते हुए अपने नियम तय कर उन्हें ग्रामसभा में प्रस्ताव के रुप में पारित भी कर रही है। साथ ही इसके मतांतरण के विरुद्ध ग्रामसभाएं पेसा एक्ट के अंतर्गत आने वाले अधिकारो का भी प्रयोग करने लगी है। इसी कड़ी में आलीराजपुर के छकतला क्षेत्र में ग्राम पंचायत अकड़िया के ग्राम चिलकदा में बीते गुरुवार को विशेष ग्रामसभा आयोजित कर ऐतिहासिक निर्णय लिया जिसे प्रस्ताव में ला कर पारित भी किया। महत्वपूर्ण प्रस्ताव में स्पष्ट किया कि जो आदिवासी परिवार अपने मूल को छोड़कर ईसाई बने चुके है वो गांव की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे। उनको शासन की योजनाओं के लाभों से दूर किया जाएगा, इसके साथ उन मतांतरित परिवारों के अंत्योष्टी संस्कार भी समाज के श्मसान घाट पर नहीं होगे, कठोरता के साथ यह भी तय किया कि, मतांतरित परिवारों को गांव से किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिलेगा। विवाहोत्सव में जिस प्रकार गांव सहयोग करता है वह भी नहीं किया जाएगा, और मतांतरित परिवार से वैवाहिक संबंध भी नहीं जोड़े जाएगे।

ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव में इस बात का समर्थन किया है कि जो मतांतरित परिवार अपने मूल धर्म में आकर अपनी मूल संस्कृति को अपनाता है तो समाज उसकी घर वापसी का सम्मान करेगा, और ग्रामसभा में उसे सम्मानपूर्वक स्वीकार कर उसे पूर्णरुप से अपनाएगा। साथ ही साथ सामाजिक तौर पर प्रस्ताव को न मानने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाही की चेतावनी भी ग्रामसभा में दी गई है।

आदिवासी संस्कृति बचाने की अनुठी पहल में ग्रामसभा में पारित किए गए सभा प्रस्ताव सर्व सहमती से किए गए है। इसी दौरान क्षेत्र के जनपद अध्यक्ष ने कहा कि, धर्म बदलने वालों को जागरुक किया जाएगा, उन्हें जनजातिय संस्कृति और परंपराओं की गहराई से समझाईश दी जाएगी जिसमें उनका विश्वास पुनः लौटकर आएगा और वे सहृदय घर वापसी करेगे। इस पवित्र विचारधारा के साथ अपने मूल धर्म की सभ्यता को

समझाते हुए, अपनी परंपराओं के गुढ़ को बताते हुए ग्रामसभाएं संगठित हो रही है, जिसके उचित परिणाम भी सामने आने लगे है। आलीराजपुर के सोंडवा विकासखंड के ग्राम मथवाड़ में एक सामाजिक, धार्मिक घटनाक्रम में एक परिवार ने विधिवत अपने मूल आदिवासी सनातन धर्म में घर वापसी कर ली। मथवाड़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इसकी जानकारी दी और बताया कि, पैसो का लालच दे कर परिवार का मतांतरण करवाया, फिर उसके बच्चों की पढ़ाई का लोभ दिया गया। अंततः जब सच्चाई का सामना जंदू पुत्र भुरलिया को हुआ और फिर जनजातिय संस्कृति की मूल परंपराओं के उसका पुनः परिचय करवाया गया जिससे सत्य की ओर समझ उसकी बढ़ती गई। उपने पुर्वजो की पद्धति को गहराई से समझकर परिवार ने सनातन धर्म में विश्वास किया और मां नर्मदा में स्नान कर विधिवत घर वापसी की।

मतांतरण विरोधी कानून पर अभी भी चुनौतियां आ रही है, विभिन्न राज्यों में मतांतरण रोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से संबंधित राज्यों को नोटीस भी दिया गया है जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।

उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश आदि के मतांतरण रोधी कानूनों को जमीयत उलमा ए हिंद और सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस जैसे संगठनों ने यह कहते हुए चुनौती दी है यह कानून अलग-अलग पंथों से संबंधित जोड़ो को परेशान करने का एक जरिया बन गया हैं। जो कि पुरी तरह से झुठ और भ्रम फैलाने वाली दलील है।

ऐसे संगठनों की तरफ से जो भी कहा जाए किंतु सच तो यह है, देश में बहुत से समुह अलग-अलग राज्यों में भोलेभाले निर्धन लोगों को छल-कपट, बल नीति, और लोभ लालच से मतांतरण कराने में लगे हुए है। इतिहास इसका साक्षी है कि भारत बहुत सी सदियों से कपट और कुटिलता के साथ लालच से मतांतरण का भुक्तभोगी है। देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद भी छल, छद्म से मतांतरण अभियान तेज गति से शुरु हो गए थे, जिसका उदाहरण जनजातिय क्षेत्र में देखा जा सकता है। ईसाई मिशनरियों ने पहले पुर्वोत्तर राज्यों के जनजाति समाज को निशाना बनाया, फिर मध्यप्रदेश, ओड़िशा में अनगिनत आदिवासी लोग ईसाई बन गए है। जिनकी दशा पहले की तरह ही है, उनमें विकास की गति को देख कर कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखा है। मतांतरण के अभियान किस तरह बेलगाम है पंजाब में उसकी सक्रियता देखी जा सकती है।

रिंकेश बैरागी

मतांतरण रोधी कानून को चुनौतियां देने वालें संगठन ऐसा कोई दावा प्रस्तुत ही नहीं कर पाएगे कि जिसमें लोभ-लालच, छल, बल, धोका, कपट, की सहायता बिना कोई व्यक्ति या परिवार मतांतरित हुआ हो। यथार्थ और सच्चाई यह प्रमाणित करती है कि, कोई भी व्यक्ति या परिवार अंतः प्रेरणा से अपने मूल सनातन धर्म को छोड़ कर न तो ईसाई बनता है न ही मुस्लिम, और न ही कोई अन्य पंथ या मजहब को स्वीकारता है। सभी मतांतरण लोभ-लालच छल कपट से किये जाते हैं।

पेसा अधिनियम के अंतर्गत अधिकारो का उपयोग और ग्रामसभाओं के शक्तिशाली संगठन और कठोर नियम के साथ ऐसे प्रस्ताव को पारित किया जाए जिसमें सनातन धर्म के विरुद्ध विचार का प्रचार करने वालों को समाज से विरक्त करने के निर्णय कठोरता के साथ लिए जाए साथ ही सनातन, संस्कृति की परंपराओं का गहनता के साथ लोगों को समझाईश दी जाए तो अवश्य ही छल, बल, लोभ से किए जाने वाले मतांतरण आंदोलन समाप्त हो सकेंगे।

त्यौहार से पहले उज्जैन में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई

माही की गूंज, उज्जैन।

दीपावली पर्व नजदीक आते ही खाद्य एवं औषधि विभाग सक्रिय हो गया है। मिलावटखोरों पर नकेल कसने के उद्देश्य से विभाग ने मंगलवार को शहर में अचानक जांच अभियान चलाया।

इस दौरान दो अलग-अलग स्थानों से कुल 200 किलोग्राम मावा और 30 लीटर घी जब्त किया गया। सभी उत्पादों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने तक इन्हें सुरक्षित रखा गया है।

पहली कार्रवाई में ई-रिक्शा से मिला मावा और घी

आगर रोड स्थित फायर ब्रिगेड कार्यालय के सामने विभागीय टीम ने एक ई-रिक्शा को रोककर जांच की। तलाशी लेने पर उसमें 75 किलोग्राम मावा और दो डब्बों में लगभग 30 लीटर घी पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंतदत्त शर्मा ने बताया कि यह माल जय श्री महाकाल डेयरी, ऐरवास गांव से आया था। मौके पर पहुंचे संदीप आंजना नामक व्यक्ति ने खुद को इन उत्पादों का खरीदार बताया। टीम ने मावा और घी के नमूने लिए और रिपोर्ट आने तक की अवधि के लिए सामग्री को संदीप आंजना की सुपुर्दगी में दे दिया गया।

दूसरी कार्रवाई, बस से आया संदिग्ध मावा जब्त

दूसरी कार्रवाई देवास गेट बस स्टैंड क्षेत्र में की गई, जहां विभागीय टीम ने बेगम बस से आई चार टोकरियों की जांच की। इन टोकरियों में करीब 100 किलोग्राम मावा भरा हुआ था। जांच के दौरान न तो कोई बिल, बिल्टी या परिवहन दस्तावेज मिले और न ही कोई व्यक्ति सामने आया, जो इस मावे का स्वामी होने का दावा करे। विभाग ने एहतियातन पूरा मावा जब्त कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि यदि निर्धारित समय में कोई व्यापारी या परिवहनकर्ता इसे लेने नहीं आता, तो नमूने लेने के बाद इस मावे को नष्ट कर दिया जाएगा।

त्योहारों पर मिलावट रोकने विशेष अभियान जारी

दीपावली के पहले मावा, घी, मिठाई और दूध उत्पादों की मांग बढ़ जाती है, जिसका फायदा मिलावटखोर उठाने की कोशिश करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग ने पूरे जिले में विशेष निगरानी अभियान शुरू किया है। सोमवार को भी अधिकारियों ने आगर रोड क्षेत्र में कार्रवाई की थी, जहां सड़क किनारे गंदगी के बीच रखा 50 किलोग्राम मावा जब्त किया गया था। बाद में उसे ट्रेंचिंग ग्राउंड में नष्ट कर दिया गया।

अधिकारियों की सख्त चेतावनी

खाद्य अधिकारी बसंतदत्त शर्मा ने बताया कि दीपावली पर्व को देखते हुए शहर में हर स्तर पर जांच अभियान जारी रहेगा। किसी भी व्यापारी या डेयरी संचालक को बिना परीक्षण के खाद्य सामग्री बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विभागीय टीम मिठाई दुकानों, डेयरियों, और थोक व्यापारियों पर विशेष निगरानी रख रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यापारी के उत्पादों में मिलावट या अस्वच्छता पाई गई, तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि वे खाद्य सामग्री खरीदते समय स्रोत और गुणवत्ता की जांच अवश्य करें।

उपभोक्ता सजग रहें, विभाग अलर्ट

खाद्य विभाग का कहना है कि त्योहारों पर बढ़ी मांग के बीच नकली मावा और घी का धंधा तेजी से फैलता है। ऐसे में विभाग का उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा करना है। इस दिशा में लगातार अभियान चलाकर संदिग्ध सामग्री को बाजार में आने से पहले ही रोका जा रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, आगामी दिनों में भी मिठाई निर्माण इकाइयों, थोक मावा आपूर्तिकर्ताओं और डेयरियों की जांच जारी रहेगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद मिलावटी पाए जाने पर जुर्माना और लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी कार्रवाई भी की जाएगी।

'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान को जन-जन तक पहुंचाकर भाजपा की नीतियों के खिलाफ जनजागरण जारी रखा जाएगा- कांग्रेस

माही की गूंज, अलीराजपुर।

राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे ÷वोट चोर गद्दी छोड़÷ हस्ताक्षर अभियान एवं बीएलए की प्रत्येक बूथ पर नवीन नियुक्ति के तहत बोरखड़ स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक मे अभियान के अलीराजपुर विधानसभा प्रभारी गिरीश जायसवाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश पटेल सहित जिलेभर के कांग्रेसी नेता ओर कार्यकर्तागण उपस्थित थे। बैठक में प्रभारी गिरीश जायसवाल ने राहुल गांधी द्वारा भाजपा की तथाकथित ÷वोट चोर नीति÷ के खिलाफ चलाए जा रहे राष्ट्रीय अभियान को गति देने पर विस्तार के बारे मे बताया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशों के अनुसार ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों, नगर अध्यक्षों व वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हस्ताक्षर अभियान के फॉर्मेट वितरित किए गए। साथ ही कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक लोगों तक अभियान को पहुंचाने के लिए प्रेरित किया गया। बैठक मे कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओ ने एकजुट होकर जिले में हजारों की संख्या मे हस्ताक्षर एकत्रित करने का संकल्प लिया।

बैठक के अंत में जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश पटेल ने कांग्रेसी नेताओं ओर कार्यकर्ताओं को यह संकल्प दिलाया कि, जिले में 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान को जन-जन तक पहुंचाकर भाजपा की नीतियों के खिलाफ जनजागरण जारी रखा जाएगा। इस अवसर पर पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओमप्रकाश राठौर, खुर्शीद अली दिवान, कमलेश पचाया, शमशेरसिंह पटेल, मदन डावर, पारसिंह बारिया, सुरसिंह भाई, सुरेश सारडा, तरुण मंडलोई, भरत राज जाधव, वेरसिंह बारिया, कालू भाई सहित अनेक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उपस्थित थे।

विकास खंड स्तरीय राष्ट्रीय पोषण आहार योजना का हुआ आयोजन

माही की गूंज, चं.शे. आजाद नगर।

विकासखण्ड स्तर पोषण माह का आयोजन नगर पंचायत अध्यक्ष की विशेष उपस्थिति में आयोजित किया गया। जिसमें महिला बाल विकास की सक्रिय कार्यकताओं ने अलग-अलग व्यंजन बनाकर प्रदर्शन में रखे जिसे सभी अतिथियों ने खाकर सभी की तारीफ भी की।

इस अवसर पर नगर? पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निर्मला डावर ने कहा कि, आप लोग यहां भोजन बनाकर लाए हैं वह अपनी खेती से उत्पन्न हुई अनाज का सेवन करें जो पौष्टिक भी रहने की बात कही । साथ ही सभी के व्यंजन की तारीफ भी की

तेहसीलदार जितेन्द्र सिंह तोमर ने कहा की यह अभियान जागरुकता की कमी के चलते मनाया जा रहा है। हम हर गांव कस्बे के लोगो को जागृत करना होगा। तोमर ने कहा, हम लोग अपने खेती से उत्पन्न हो रही है ज्यादा से ज्यादा वही खायें हमें खुद को यह जागरूकता लानी होंगी। हमें आंगनवाड़ी में भी अच्छा खाना दे यह हमारी जुम्मे दारी है। ताकी बच्चा कुपोषण ना हो बच्चे भी आपके व आपके गांव के ही हैं आज हमारे जिले के कलेक्टर व एसडीएम आजाद नगर भाबरा दोनों महिलाएं हैं इसलिए महिला सशक्तिकरण में विशेष ध्यान रहेगा। इसलिए आप सभी जागरूक रहें ताकि शासन की योजना का लाभ ज़मीन स्तर तक पहुंचाएं।

जनपद पंचायत सीईओ इंदरसिंह पटेल ने कहा कि, पोषण आहार योजना में गर्भवती महिलाओं को ज्यादा तर ध्यान देने की जरूरत है। हरी सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश करें। ताकी मां व बच्चा भी स्वस्थ रहें।

परियोजना प्रभारी श्रीमती मेरी चौहान ने कहा कि, हमारी कार्यकर्ताओं से व्यंजन बनाकर लाने पर ध्यान दिया और साथ ही कुपोषित बच्चों को भर्ती करवाने का भी आह्वान किया।

किरण मेडम ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा की बाजार की कोई चीज़ ना खिलाकर घर में बनी सब्जी दालों का उपयोग करें। जनपद सदस्य शेलेश गोहिल ने भी सम्बोधित किया।

आयोजन में विभाग प्रमुख श्रीमती मेरी चौहान, (प्रभारी परियोजना अधिकारी), सेक्टर पर्यवेक्षक श्रीमती किरण गणावा, सुश्री शांता बामनिया, श्रीमती सुशिला चमेलका, श्रीमती सविता मण्डलोई, कृष्णपालसिंह जादव (सहा ग्रेड 03), सचिन चौहान (ब्लॉक समन्वयक) रियाजउददीन कुरैशी (ऑपरेटर) राजेश तोमर (भृत्य) एवं समस्त कार्यकर्ता, सहायिका कार्यक्रम मे उपस्थित रहे।

महाकाल मंदिर परिसर में नहीं फोड़े जाएंगे पटाखे

माही की गूंज, उज्जैन।

दीपावली पर्व को लेकर श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति ने अहम निर्णय लिया है। धार्मिक परंपरा और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से मंदिर परिसर में आतिशबाज़ी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

मंदिर समिति ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष दीपावली के दिन भगवान श्री महाकालेश्वर की सभी आरतियों प्रातः भस्म आरती, अभ्यंग स्नान पश्चात आरती, संध्या आरती और शयन आरती में पूजा का एक प्रतीकात्मक हिस्सा होते हुए सिर्फ एक फूलझड़ी जलाई जाएगी। मंदिर प्रशासन ने कहा कि, यह परंपरा वर्षों से चली आ रही धार्मिक मर्यादा के अनुरूप निभाई जाएगी, जिसमें सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से दीपोत्सव का भाव प्रकट किया जाता है, न कि ध्वनि या प्रदूषण फैलाने वाली आतिशबाज़ी से। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि गर्भगृह, कोटीतीर्थ कुण्ड, मंदिर परिसर और श्री महाकाल महालोक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आतिशबाज़ी जैसे अनार, बम, फुलझड़ी या अन्य ज्वलनशील सामग्री को लाना, रखना या जलाना पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं और नागरिकों से अपील की है कि वे दीपावली को शांतिपूर्ण, पारंपरिक और श्रद्धाभाव से मनाएँ तथा मंदिर प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मंदिर प्रबंधन ने कहा कि यह निर्णय श्रद्धालुओं की सुरक्षा और धार्मिक अनुशासन की भावना से लिया गया है, और सभी से सहयोग की अपेक्षा की गई है।

त्योहारों में मिलावटी सामग्री एवं खाद्य पदार्थों पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के निर्देश

माही की गूंज, बरझर।

आगामी त्योहारों में मिलावटी सामग्री एवं खाद्य पदार्थों पर रोकथाम करने के निर्देश कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने समीक्षा बैठक के दौरान समस्त अनुविभागीय एवं संबंधित अधिकारी को दिए। निर्देशों के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी चंद्रशेखर आजाद नगर सुश्री निधी मिश्रा द्वारा चंद्रशेखर आजाद नगर के ग्राम बरझर के मुख्य बाजार एवं अन्?य स्?थानों पर खाद्यान्न सामग्री की जांच की। इस दौरान श्री श्याम होटल, ओम साईराम होटल, मुकेश किराना, आशीष किराना एवं जनरल स्?टोर, आदि स्थानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एक्सपायरी खाद्य सामग्री जब्त कर नष्ट करने के साथ भविष्?य के लिए चेतावनी दी गई एवं खाद्य सामग्री के लिए सैम्पल लिए गए। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

फ्लाइंग किस की बात पर भिड़ गए दो पक्ष

माही की गूंज, धार/अमझेरा।

स्थानीय अंबिका रोड पर को एक विवाद ने उग्र रूप ले लिया, जब कथित तौर पर फ्लाइंग किस की हरकत पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस घटना में दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं। मारपीट में लाठी-डंडों, मुक्कों और तलवार का इस्तेमाल किए जाने की भी बात सामने आई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किए हैं।

घटना सीसीटीवी में कैद

उक्त घटना रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। अमझेरा पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार अंबिका रोड निवासी 23 वर्षीय फरियादी युवती ने बताया कि घटना के समय तीन आरोपितों ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ा और उसे फ्लाइंग किस दी। फरियादी के अनुसार जब उसने इस हरकत का विरोध किया, तो आरोपित भड़क गए। उन्होंने गालियां दीं और हाथों, थप्पड़ों व डंडों से मारपीट की। इसमें चार लोगों को चोटें आई हैं।

छह लोगों को आई चोट

आरोपितों ने सभी को जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की शिकायत पर भोई मोहल्ला निवासी नौ लोगों को नामजद किया है। दूसरे पक्ष ने पुलिस को बताया कि अंबिका रोड निवासी आरोपितों ने उनका रास्ता रोका। गालियां देकर थप्पड़, मुक्के, डंडे और तलवार से मारपीट की। इसमें छह लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों पर प्रकरण दर्ज किए हैं।

अतिथि शिक्षक ने सहायक आयुक्त से की मुलाकात, नही मिला तीन माह का वेतन

माही की गूंज, चं.शे. आजाद नगर।

आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ ने अगस्त से अक्टूबर 2025 तक 3 माह तीन माह से मानदेय नहीं मिलने के संबंध में समस्त अतिथि शिक्षकों ने सहायक आयुक्त को ज्ञापन सौपा। अतिथि शिक्षको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा रहा है। सहायक आयुक्त ने आश्वासन दिया कि, दीपावली के पूर्व किया जायेगा। एवं एवं समस्त बीईओ को निर्देशित कर दिया गया है व्हाट्सएप के माध्यम से यही आश्वासन दिया।

इस अवसर पर उपस्थित जिला अध्यक्ष भीका गणावा, जिला सचिव लोंगसिंह चौहान, जिला उपाध्यक्ष हीरु कनेश, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष आजम चौहान, जिला मीडिया प्रभारी हितेश अलावा, भाबरा ब्लॉक अध्यक्ष अल्केश सोलंकी, ब्लॉक उपाध्यक्ष राकेश जमरा, अलीराजपुर ब्लॉक से सुभान सिंह डावर, ललित रावत, भाबरा ब्लॉक से दिनेश भूरिया, उदयगढ़ ब्लॉक कैलाश मंडलोई, दिनेश कनेश, कट्ठीवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष हरसिंह धाकड़, आमखुट संकुल से महेश मंडोरिया, दीपमाला गुप्ता, सुनीता डुडवे, प्रियंका शर्मा, सीमा भाबर, सोन ज्योति, तेजू तोमर एवं समस्त अतिथि शिक्षक संघ उपस्थित थे।

बेटा-बहू की बेरहमी

पहली घटना में घर से निकाल कर दिया खाना-पीना बंद, तो दूसरी में जमीन विवाद को लेकर बाप की कर दी पिटाई

माही की गूंज, उज्जैन।

संस्कारों और पारिवारिक मूल्यों की धरती उज्जैन में मंगलवार को दो चौंकाने वाली घटनाएं सामने आईं, जिन्होंने रिश्तों की मर्यादा को झकझोर दिया। पहली घटना में ग्राम गोयला के एक वृद्ध दंपत्ति को उनके ही बेटे-बहू ने घर से निकालकर खाना देना बंद कर दिया, जबकि दूसरी घटना में ग्राम नलेसरी में एक बेटे ने जमीन विवाद को लेकर अपने 65 वर्षीय पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी। दोनों ही मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

ग्राम गोयला, उन्हेल रोड निवासी सेवाराम आंजना और उनकी पत्नी अपने बेटे कमल और बहू राधा के साथ रहते थे। कुछ समय से दोनों बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना का सिलसिला चल रहा था। आरोप है कि बेटे-बहू ने उन्हें भोजन देना बंद कर दिया और फसल में से हिस्सा मांगने पर घर से निकाल दिया। भूख और अपमान से व्यथित होकर वृद्ध दंपत्ति भेरूगढ़ थाने पहुंचे और बेटे-बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कमल और राधा को गिरफ्तार किया। दोनों को बुधवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

भेरूगढ़ थाना प्रभारी के अनुसार, ÷वृद्ध दंपत्ति की शिकायत के बाद हमने दोनों आरोपियों के खिलाफ वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। माता-पिता की सेवा करना संतान का कर्तव्य है, और जो ऐसा नहीं करते, उन्हें कानून सजा देगा।÷ स्थानीय लोगों ने भी इस मामले में आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज में मिसाल कायम हो सके।

दूसरी घटना कायथा के समीप ग्राम नलेसरी की है, जहां 65 वर्षीय अजीज पिता नमीर बश को उनके ही बेटे इमरान ने जमीन विवाद को लेकर पीट-पीटकर घायल कर दिया। घटना के बाद गंभीर हालत में अजीज को चरक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में भर्ती अजीज ने बताया कि उनका बेटा अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो पहले ही आठ बीघा जमीन में से चार बीघा धोखे से बेच चुका है। अब वह बाकी जमीन भी हड़पने की कोशिश कर रहा था। जब अजीज ने इसका विरोध किया तो इमरान खेत पर पहुंचा और उन पर हमला कर दिया। अजीज ने बताया कि बेटे के इस व्यवहार से वह काफी दिनों से परेशान हैं। ग्रामीणों के मुताबिक, इमरान आए दिन विवाद करता है और परिवार के सदस्यों को धमकाता रहता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लगातार बढ़ रहे पारिवारिक हिंसा के मामले

इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर समाज में बढ़ती पारिवारिक हिंसा और नैतिक पतन की तस्वीर उजागर कर दी है। बुजुर्गों के प्रति अनादर और हिंसा के ऐसे मामलों में कानून सख्त है, लेकिन सामाजिक स्तर पर संवेदनशीलता और संस्कारों की कमी सबसे बड़ी चिंता का विषय बनती जा रही है। समाजसेवी संगठनों ने इन घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में न केवल कानूनी कार्रवाई, बल्कि समाज में जागरूकता अभियान चलाना भी जरूरी है ताकि लोग अपने बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील बनें।

पुलिस का सख्त रुख

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम के तहत त्वरित कार्रवाई की जा रही है। किसी भी परिवार में यदि बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार या हिंसा होती है, तो संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कर तुरंत कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि, इन दोनों घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि जब परिवारों में मान-सम्मान और संवेदना खत्म हो जाती है, तो रिश्ते केवल नाम के रह जाते हैं। समाज को ऐसे मामलों से सबक लेकर अपने बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा के लिए आगे आना होगा।

दो मेडिकल की करी जांच

माही की गूंज खवासा।

एमपी के छिंदवाड़ा जिले में जिस कफ सिरप से बच्चों की मौत हो गई उसको लेकर पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। साथ ही अब प्रत्येक जिले में ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा हर मेडिकल पर जांच की जा रही है कि, कहीं इस कंपनी का सिरप अन्य जिले में तो सप्लाई नहीं हुआ है। इसकी जांच करने के लिए प्रदेश सरकार ने ड्रग्स इंस्पेक्टर को तत्परता से सभी मेडिकल की जांच करके जहां भी कोल्ड ड्राफ्ट सिरप पाया जाता है तो उसको तत्काल नष्ट करे तथ अन्य कमियो पर भी मेडिकल पर कार्रवाई करना है। इसके बाद सभी जिले के ड्रग्स इंस्पेक्टर ने प्रत्येक मेडिकल का निरीक्षण व जाँच शुरू की। इसी कड़ी में झाबुआ जिले की ड्रग्स इंस्पेक्टर गीतम पथोरिया भी झाबुआ जिले के मेडिकल क्षेत्र में निरीक्षण करते हुए जाँच करने के लिए राजस्व विभाग की टीम के साथ पहुंच रही हैं।

जानकारीनुसार खवासा उप तहसील के अंतर्गत संचालित सभी मेडिकल पर निरीक्षण करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर गीतम पथोरिया ने बुधवार दोपहर में पहुंची। जहां दो मेडिकल का निरीक्षण किया गया और सभी दवाइयां को चेक किया गया।

ड्रग इंस्पेक्टर के साथ राजस्व विभाग के खवासा नायब तहसीलदार राजेश जमरा व पटवारी दिनेश राणा के साथ मेडिकल पर जांच की। लेकिन मैडम ने मां उमिया मेडिकल व राघवेंद्र मेडिकल हनुमान चौक गली पर संचालित सिर्फ दो मेडिकलों का निरीक्षण किया गया। बाकी मेडिकलों का कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया।

जिससे साफ प्रतीत होता है कि मैडम ने खवासा में भी रस्म निभाई और वापस झाबुआ की ओर चल दि। जबकि मैडम को बुधवार के दिन पूरा दिन खवासा मे सभी मेडिकल का निरीक्षण करना था। उसके बाद जिले की ओर रवाना होना था। लेकिन मैडम ने यहां तो कुछ मेडिकलों का निरीक्षण ही नहीं किया जिसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर मिलती। तो वही जो मेडिकल किसी अन्य के नाम से संचालित हो रहे हैं और कोई अन्य व्यक्ति बैठता है उसमे कई मेडिकल संचालक सटल बंद करके अपने घर की ओर निकल गए।

वही ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल का निरीक्षण किया तो झोलाछाप डॉक्टर अपनी दुकान बंद करके उस दोरान रफू चक्कर हो गए।

मध्यान्ह भोजन में कलेक्टर की त्वरित कार्रवाई सराहनीय पर अब शिकायतकर्ता को मिल रही धमकियां

कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम श्री मंडलोई पहुचे कार्रवाई हेतु पाटडी।

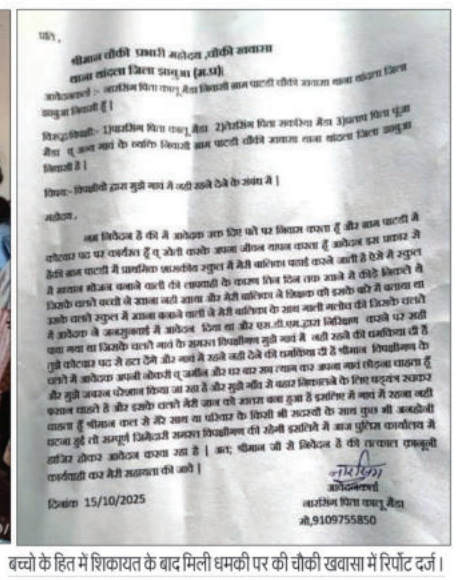

बच्चो के हित में शिकायत के बाद मिली धमकी पर की चौकी खवासा में रिर्पोट दर्ज।

माही की गूंज, खवासा/झाबुआ।

मध्याह्न भोजन में किस तरह की मनमानी व लापरवाही की जा रही है और किस तरह से घटिया ही नहीं बल्कि कीड़ा युक्त खाद्यान्न सामग्री का उपयोग कर बच्चों को कीड़ा युक्त आहार, भोजन के रूप में दिया जाने लगा है। जिसका एक मामला कलेक्टर जनसुनवाई शिकायत में सामने आया है।

कलेक्टर ने भी जनसुनवाई में आई उक्त शिकायत को गंभीरता से लिया और शिकायत दिनांक मंगलवार को ही कलेक्टर नेहा मीणा के निर्देश पर थांदला एसडीएम महेश मंडलोई जांच करने हेतु थांदला जनपद के ग्राम पंचायत पाटड़ी पहुंचे। पाटडी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन रजिस्टर का अवलोकन किया। तथा बच्चों से मध्याह्न भोजन की वस्तु स्थिति जानी गई।

बच्चों के माध्यम से एसडीएम श्री मंडलोई के सामने आया कि, 8 अक्टूबर को कीड़ों वाला मध्याह्न भोजन बच्चों को मसूर की दाल व रोटी के रूप में परोसा गया। बच्चों ने भोजन में कीड़े देखे व खाना नहीं खाने के साथ वस्तु स्थिति शिक्षकों के सामने भी आई। लेकिन उक्त अनियमित्ता जो की स्कूल में पढ़ रहे मासूम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य से जुडा होने के बावजूद वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी व शिकायत शारदा बचत समूह के संबंध में नहीं की गई। नतीजन 8 अक्टूबर के बाद आगे दो दिनों तक भी जो मध्याह्न भोजन परोसा गया उसमें कीड़े ही थे। जिसकी वजह से बच्चों ने भोजन नहीं किया। बच्चों को उम्मीद थी कि, पदस्थ शिक्षकगण मामले को गंभीरता से लेकर समूह के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाएगी लेकिन तीन दिनों तक कीड़े वाला भोजन बच्चों को परोसा गया।

उक्त गंभीर मामला बच्चों की मुंह जुबानी भी एसडीएम के सामने आया। जिसके पश्चात एसडीएम ने जांच का प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया व कलेक्टर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मध्याह्न भोजन देने वाले समूह की सेवा समाप्त के निर्देश दिये गए।

आगे मामले में उक्त मामला दबाने वाले शिक्षकों या अन्य पर क्या कार्रवाई होती है...? यह तो आगे ही पता चलेगा। परंतु कलेक्टर द्वारा जनसुनवाई में मिली उक्त शिकायत पर मामले को गंभीरता से लिया और त्वरित जाँच का आदेश देकर जांच करवाई उक्त त्वरित कार्रवाई राहनीय है। साथ ही उम्मीद करते हैं कि, इस तरह के घटिया मध्याह्न भोजन के मामले होते हैं लेकिन इसे दबाए जा रहे हैं। ऐसे में एक जनपद स्तर पर एक विशेष जॉच दल गठित की जाए जो अचानक क्षेत्र की किसी न किसी स्कूल का निरीक्षण मध्याह्न भोजन के समय निरंतर किया जाए। तो इस तरह की अनियमिताएं नहीं आएगी और बच्चों के स्वास्थ्य के संबंध में भी कोई डर नहीं रहेगा।

बच्चों के हित में की शिकायत पर अब मिल रही धमकी

भला करो तो हो बुरा की कहावत शिकायतकर्ता पर अमल हो रही है। कीड़े युक्त मध्याह्न भोजन की शिकायत मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई में पाटड़ी के कोटवाल नारसिंह पिता कालू मेड़ा ने अपनी पुत्री खुशबू के साथ समूह एवं खाना बनाने वाली महिला के विरुद्ध बच्चों एवं गांव के हित में की। उक्त शिकायत पर कलेक्टर ने त्वरित कार्रवाई की जिसकी सराहना भी की जा रही है। मगर उसके उलट एक दूसरा दृश्य भी उक्त मामले में देखने को मिल रहा है। जिसमे नारसिंह अनुसार बताया जा रहा है कि, परिवार व गाव के ही लोग, समूह संचालकों द्वारा भडकाए जाने पर जनसुनवाई में की गई शिकायत व उस पर हुई कार्रवाई पर धमकाया जा रहा है। तथा तुझे कोटवाल पद से हटवा दिया जाएगा और गांव में नहीं रहने देंगे की धमकियां मिल रही रही है। वहीं खाना बनाने वाली जाना पारसिंह मेडा ने उसकी पुत्री एवं स्कूल की छात्रा को गाली-गलौज दी जा रही है। इस संबंध में खवासा चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है।

खबरदारः यमराज बनकर जिले की सड़कों पर दौड़ रहा 2023 में एक्सपायर हुआ भावांतर योजना का प्रचार रथ

न रजिस्ट्रेशन रिनिवल, न बीमा, न फिटनेस फिर भी कलेक्टर के निर्देशन में अपर कलेक्टर ने वाहन को दिखा दी हरी झंडी

माही की गूंज, झाबुआ।
मुजम्मिल मंसुरी

वर्तमान में किसानों की बिगड़ी सोयाबीन फसल को लेकर सरकार ने भावांतर योजना लागू की। इस योजना के लागू होते ही पूरे प्रदेश में चारों ओर हल्ला हो गया। किसानों ने इस योजना को ठगी करार दे दिया। योजना के संबंध में एक अलग ही चर्चा की जा सकती है, किसानों को लाभ होगा या नहीं...? भावांतर योजना कितनी सार्थक हो सकती है...? सरकार का इस योजना पर क्या रूख है...? इस तरह की तमाम बातें, मगर अभी मामला कुछ ओर ही है।

वैसे तो जिले में कई योजनाएं संचालित हो रही है लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ ओर ही बयां करती नजर आती है। अधिकारी अपने कार्यालयों में बैठकर हथेली में दिल्ली और अंगूठे में कुतुब मीनार बताते नजर आते है। विडम्बना यह कि अब कलेक्ट्रोरेट या शासकीय कार्यालयों में कई आयोजनों से पत्रकारों को दूर ही रखा जाता है। प्रति मंगलवार होने वाली जनसुनवाई हो, समयावधि पत्रों की बैठक हो या फिर कुछ ओर आयोजन पत्रकारों के प्रवेश पर लगभग प्रतिबंध सा लगा हुआ है। ना पत्रकार वहां से कोई जानकारी ले सकता है और ना ही किसी तरह के फोटो खींच सकता है। जो कुछ भी समाचार या फोटो कार्यालयों के बाहर मीडिया में जाएंगे वह सिर्फ और सिर्फ पीआरओ कार्यालय से ही जाएंगे...! मतलब सीधा सा यह है कि, पीआरओ कार्यालय से जो खबरें निकलेंगी वह सिर्फ प्रशासनिक कागजी उपलब्धियों का पुलिंदा होंगी, जो प्रशासन की सिर्फ और सिर्फ वाहवाही ही बयान करेंगी। जिसका सीधा फायदा अधिकारियों को यह मिलता है कि, वे अपनी मर्जी से कुछ भी काम करने से हिचकते नहीं है। नतीजा यह निकलकर सामने आता है कि, मीडिया का खौफ अधिकारियों के मन से निकलता जा रहा है और वे वही करते है जिसमें सिर्फ फायदा ही फायदा हो।

झाबुआ कलेक्टोरेट से भावांतर योजना के तहत 2023 में एक्सपायर हो चुके वाहन को प्रचार के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करते अपर कलेक्टर और अन्य अधिकारी।

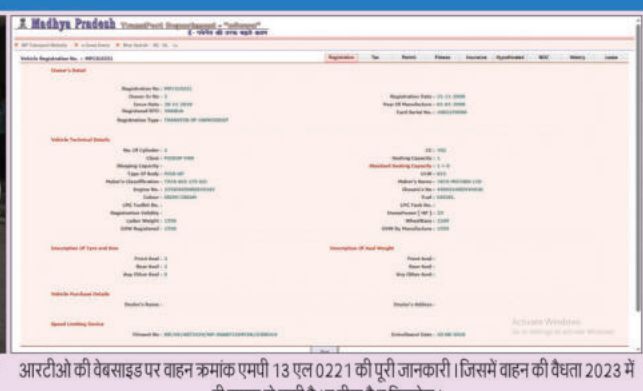

आरटीओ की वेबसाइड पर वाहन क्रमांक एमपी 13 एल 0221 की पूरी जानकारी। जिसमें वाहन की वैधता 2023 में ही समाप्त हो चुकी है। न बीमा है न फिटनेस।

एक ऐसा ही मामला पिछले दिनों 9 अक्टूबर को कलेक्ट्रोरेट कार्यालय में देखने को मिला। अवसर यह था कि, भावांतर जैसी योजना का प्रचार-प्रसार करने हेतु सरकारी आदेश पर अधिकारियों ने कमर कसी थी। कलेक्ट्रोरेट कार्यालय से एक प्रचार वाहन इसी भावांतर योजना के प्रचार के लिए कलेक्टर नेहा मीणा के निर्देशन में अपर कलेक्टर चंदर सिंह सोलंकी द्वारा रवाना किया गया। अधिकारियों ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाई, फोटो खिंचवाए और पीआरओ ने इसके लिए प्रेसनोट जारी किया। यह और बात है कि, पीआरओ द्वारा जारी प्रेसनोटों को स्थानीय मीडिया में जगह मिली या नहीं। क्योंकि इस तरह के आयोजनों को लेकर प्रशासन किसी भी मीडिया संस्थान को कोई सूचना देना उचित नहीं समझता।

वैसे तो यह सारा मामला सामान्य सा नजर आता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा झोल सामने निकल कर आया है। जिस वाहन क्रमांक एमपी 13 एल 0221 (टाटा एस 275 आईडीआई) को भावांतर योजना के प्रचार के लिए अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाई थी वह वाहन रिकार्ड पर पूरी तरह से कंडम हो चुका है। जिसका न तो रजिस्ट्रेशन रिनिवल है, ना बीमा है और ना ही फिटनेस...? अब सवाल यह कि, यह वाहन आखिर इस तरह के शासकीय कार्य में किस तरह से लगाया गया...? क्या अधिकारियों ने वाहन लगाने से पहले इसकी पूर्ण रूप से जांच की थी...? या फिर यहां भी कमीशन के फेर में अधिकारियों ने इस तरह की हरकत कर डाली...?

जब हमने भावांतर योजना में लगे इस वाहन की विस्तृत जानकारी एमपी आरटीओ की वेबसाइड पर देखी तो जो स्थिति निकलकर सामने आई वह यह थी कि, उक्त गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 2023 में ही खत्म हो चुका है। फिटनेस 2019 के बाद करवाया ही नहीं गया। गाड़ी का बीमा भी 2023 के बाद करवाया ही नहीं गया। गाड़ी का पीयूसी भी बना हुआ नही है। गाड़ी की एनओसी झाबुआ आरटीओ में ही है। मगर अधिकारियों को इससे क्या मतलब? उन्हे तो बस फोटो खिंचवाना था और अखबारों से सुर्खियां बटोरनी थी।

अब कल्पना किजिए कि, जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रोरेट कार्यालय से जिस वाहन को झंडी दिखाई गई हो उसकी स्थिति यह है तो फिर अधिकारियों की कार्यप्रणाली किस तरह की होगी। विडम्बना यह कि, यह कार्य कलेक्टर नेहा मीणा के निर्देशन में खुद अपर कलेक्टर चंदर सिंह सोलंकी द्वारा किया गया। हो सकता है इसमें गलती कलेक्टर या अपर कलेक्टर की ना हो लेकिन यह तय है कि, उन्ही के किसी अधिनस्त अधिकारी ने इस पूरी योजना को अंजाम दिया होगा। गाड़ी प्रचार में लगाने हेतु किसी न किसी अधिकारी ने तो वाहन मालिक से बात की होगी। गाड़ी का किराया-भाड़ा तय किया गया होगा। उसके बाद ही वाहन को प्रचार के लिए रवाना किया गया होगा। यहां कई सवाल अधिकारियों पर उठते नजर आते है। क्या प्रचार वाहन के अनुबंध संबंधी कोई निर्देश, आदेश या कोई अनुज्ञा जारी की गई? अगर ऐसा नही हुआ तो फिर क्या अधिकारियों ने अपनी जेब से खर्च कर प्रचार वाहन रवाना किया...? क्यों शासकीय कार्य में उपयोग लेने हेतु गाड़ी के कागजात चेक नहीं किए गए...? या फिर जिस अधिकारी कर्मचारी के जरिए यह वाहन लगाया गया उसमें कमीशन का खेल खेला गया?

अब जरा कल्पना कीजिए कि, जिस भावांतर योजना के प्रचार के लिए कलेक्टर नेहा मीणा के निर्देशन में अपर कलेक्टर चंदर सिंह सोलंकी ने जो वाहन रवाना किया है अगर वह किसी दुर्घटना का शिकार होता है या उस वाहन से किसी तरह की कोई जनहानी होती है, तो फिर क्या होगा...? क्या दुर्घटना में हताहत होने वाले लोगों को क्लेम मिल सकेगा...? जबकि वाहन पूरी तरह से सरकारी गाइड लाइन के अनुसार उपयोग अवधी से बाहर हो चुका है। अगर यह वाहन दो-चार दिन पहले, एक दो माह पूर्व उपयोग अवधी से बाहर होता तो बात समझी जा सकती थी। लेकिन स्थिति यह है कि 2023 के बाद से ही यह वाहन उपयोग अवधी से बाहर हो चुका है। न बीमा है, न फिटनेस। बावजूद इसके यह वाहन अब भी जिले की सड़कों पर यमराज बनकर दौड़ रहा है और विडम्बना यह कि, अब वह शासकीय योजना के प्रचार हेतु दौड़ रहा है।

यह तो सिर्फ एक मामला था जो अचानक अनचाहे ही उजागर हो गया, लेकिन सोचा जा सकता है कि, कलेक्ट्रोरेट के गलियारे से ऐसे कई योजनाओं के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाई जाती है। मगर कभी किसी ने ऐसी कल्पना नही की थी कि, कलेक्ट्रोरेट में बैठे अधिकारी इस तरह की लापरवाहियां करते हुए आमजन की जान से खिलवाड़ करते होंगे। हम यहां कतई दावा नही करते कि, कलेक्टाोरेट से योजनाओं के प्रचार में उपयोग किए जाने वाले सभी वाहन इस तरह के हो सकते है। लेकिन अब यह एक तरह का मामला उजागर हुआ है तो शंका और सवाल दोनों ही उठाता नजर आ रहा है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422